● वर्ष-5
● अंक-194
रायपुर, बुधवार
01 अप्रैल 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ...

डेडलाइन के अंतिम दिन 1.47 करोड़ के इनामी 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर

93 हथियार, 2.90 करोड़ कैश और 7 किलो से अधिक सोना बरामद

बस्तर । नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के अंतिम दिन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 25 नक्सलियों ने हथियारों के साथ समर्पण किया। इनमें 12 महिला और 13 पुरुष नक्सली है। सभी 1 करोड़ 47 लाख रुपए के ईनामी नक्सली हैं. इनसे माओवादी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की गई है. 2 करोड़ 90 लाख रुपए कैश और 11.16 करोड़ का 7.20 किग्रा सोना बरामद हुआ है. वहीं एलएमजी, एके-47, एसएलआर, इंसास जैसे 93 घातक हथियारों भी सौंपे गए हैं।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख रुप सें सी4पीसी मंगल कोरसा ऊर्फ मोटू, सी4पीसी आकाश ऊर्फ फ ागु उईका, DVCM शंकर मुचाकी, (पश्चिम बस्तर डिवीजन प्लाटून नंबर 12 कमांडर),एसीएम राजू रैयाम ऊर्फ मुन्ना,एसीएम पाले कुरसम जैसे वरिष्ठ माओवादी कैडर शामिल है, जिन्हाने संगठन की औचित्यहीनता को स्वीकार करते हुए राष्ट्र की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है।

यह हथियार हुए बरामद: 4 नग एके-47 रायफ्ल, 9 नग एसएलआर रायफ्ल, 1 नग इंसास एलएमजी, 07 नग 5.56 इंसास रायफ्ल, 1 नग कार्बाइन, 12 नग 303 रायफ्ल, 1 नग 8 एमएम पिस्टल, 7 नग सिंगलशॉट, 23 नग बीजीएल लांचर, 3 नग 315 बोर, 14 नग 12 बोर सहित कुल 93 हथियार बरामद किया गया है।

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ गढ़ेगा विकास का स्वर्णिम भविष्य: मुख्यमंत्री साय

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति की दिशा में मिली ऐतिहासिक सफ्लता के बीच आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर शर्मा ने मुख्यमंत्री को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में मिली इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ अब विकास, विश्वास और समृद्धि के नए युग की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद वर्षों तक प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बना रहा और विशेष रूप से बस्तर अंचल लंबे समय तक लाल आतंक के साये में रहा।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और नक्सल प्रभावित सभी क्षेत्रों में विकास की मुख्यधारा मजबूत हो रही है। बस्तर सहित पूरे प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास का नया वातावरण तैयार हो रहा है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प, स्पष्ट नीति और प्रभावी रणनीति को दिया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भयमुक्त और सुरक्षित छत्तीसगढ़ का सपना आज साकार हो रहा है।मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शहादत ने इस सफ्लता की नींव रखी है। उन्होंने सुरक्षाबलों के अदम्य साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके अथक प्रयासों का परिणाम है।मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नक्सलमुक्त वातावरण में अब छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास के नए सोपान गढ़ेगा और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।

18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

सोनिया वोटर लिस्ट केस में याचिकाकर्ता से सवाल

नईदिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नाम को लेकर दाखिल रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कई अहम सवाल किए गए। ये मामला में आरोप लगाया गया है कि बिना भारत की नागरिकता हासिल किए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि वह इतने पुराने मामले में केस दर्ज करने की मांग क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला लगभग आधी सदी पुराना है, ऐसे में जांच किसकी और किस आधार पर की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में जो जानकारी दी जा रही है, वो सिर्फ नाम जोड़ने और हटाने की परिस्थितियों तक सीमित है। इस मामले का दायरा बढ़ाने की कोशिश हो रही है।याचिकाकर्ता के वकील विकास त्रिपाठी की दलीलें पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये एक विदेशी नागरिक के गलत घोषणा का मामला है। वकील ने कहा कि इस तरह का काम केवल जाली दस्तावेजों या धोखाधड़ी के जरिए ही संभव हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मतदाता सूची की सत्यापित प्रतियां प्राप्त की गई हैं। प्रथम दृष्टया गलत घोषणा का मामला बनता है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से जाली दस्तावेजों और जालसाजी की जांच कराने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से दलीलें अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। इससे पहले दाखिल जवाब में याचिका को तथ्यहीन, राजनीति से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया था।

चीनी सीसीटीवी कैमरों पर भारत में पाबंदी

नईदिल्ली। भारत में सीसीटीवी कैमरों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। ये फैसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जिन कैमरों को लोग अपने घर और ऑफिस की सुरक्षा के लिए लगा रहे थे, वही अब खतरे की वजह बनते दिख रहे हैं।पिछले कुछ समय से भारत में सीसीटीवी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने भी कई रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताया है कि कैसे भारत में ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे खतरे में हैं। इसकी वजह सिर्फ कमजोर सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि पॉलिसी भी है। क्योंकि भारत में धड़ल्ले से कम सिक्योरिटी वाले चीनी सीसीटीवी कैमरे बेचे जा रहे हैं।

कांग्रेस फैला रही डर, स्थिति नियंत्रण में है: प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को कहा कि भारत की प्रभावी विदेश नीति और नागरिकों की अटूट एकता ने ऊर्जा आपूर्ति से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ऐसे समय में भय फैलाने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया जब एकता अत्यंत आवश्यक है। गुजरात के वाव-थारद में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं ङ्क विशेष रूप से डीजल, पेट्रोल और गैस ङ्क को लेकर वैश्विक स्तर पर कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। फिर भी, ऐसे संकट के बीच भी भारत ने सफलतापूर्वक स्थिति को नियंत्रण में रखा है। इस सफलता का आधार देश की प्रभावी विदेश नीति और नागरिकों की अटूट एकता है।

मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम एशिया संघर्ष को और तीव्र करना चाहती है ताकि उसे राजनीतिक लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश को एकता और एकजुटता की आवश्यकता है, तब कांग्रेस नेता विभाजनकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भय और अफवाहें फैलाने में व्यस्त है। कांग्रेस सक्रिय रूप से जनता को भड़का रही है। राजनीतिक गिद्धों की तरह, कांग्रेस इंतजार कर रही है कि संकट बढ़ेगा ताकि वह स्थिति का फायदा उठाकर राजनीतिक लाभ उठा सके। अपने भाषण के बाद, मोदी ने वाव-थारद में एक रोड शो में भाग लिया, जहां सैकड़ों लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए एकत्रित हुए।

इससे पहले उसी दिन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोझिकोड में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वित्तीय भूकंप की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि वहां क्या घटनाक्रम चल रहा है। एक त्रासदी घट रही है। और कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहां होगा, यह कहां तक ??जाएगा। और केरल के लोग, भारत के लोग, इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई बढ़ेगी। एक भूकंप, एक वित्तीय भूकंप, आने वाला है।

प्रमुख समाचार

अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा: ट्रंप

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा। देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो होर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि अगर देश चाहें, तो हिम्मत दिखाएं और खुद होर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले लें। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है। अब बाकी देश खुद जाकर अपना तेल ले सकते हैं। मअमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयरस्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला सोमवार रात को किया गया। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है।

बंगाल चुनाव बुरी तरह हार रही बीजेपी: अखिलेश

लखनऊ। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी हलचल का असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी साफ दिखाई देने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि क्दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी।क्अखिलेश यादव ने ङ्क पर एक पोस्ट शेयर करते एक अखबार की कटिंग भी लगाई, जिसमें पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और बीडीओ के तबादलों का उल्लेख था। इसी मुद्दे को आधार बनाकर उन्होंने भाजपा पर सवाल खड़े किए। अपने पोस्ट में उन्होंने तीन हिस्सों में अपनी बात रखी। पहले हिस्से में उन्होंने साफ कहा कि भाजपा बंगाल में बुरी तरह हार रही है। दूसरे हिस्से में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि भाजपा अपनी क्असम्मानजनक हारक्की तैयारी कर रही है।

भाजपा का डीएमके सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल और राज्य भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके सरकार के खिलाफ आरोपपत्र जारी किया। भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदराजन, के अन्नामलाई और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। पीयूष गोयल ने कहा कि यह चुनाव तमिलनाडु के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। यह चुनाव डीएमके, कांग्रेस और उनके सहयोगियों के अपवित्र यूपीए गठबंधन को हमेशा के लिए बेनकाब कर देगा, जो तमिलनाडु में अब तक की सबसे खराब सरकारों में से एक है। गोयल ने कहा कि यह सरकार एक ही परिवार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, सांसद कनिमोजी... पूरा परिवार तमिलनाडु राज्य को लूटने में लिप्त है।

ईरान में हो चुका सत्ता परिवर्तन: पीट हेगसेथ

वॉशिंगटन। ईरान में हो चुका सत्ता परिवर्तन': पीट हेगसेथ बोले- समझौता करो वरना बड़े हमले होंगे, नाटो पर फैसला जल्द ईरान को लेकर दुनिया की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इस बयान के साथ ही अमेरिका ने साफकर दिया है कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस्त्राइल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच यह बयान ऐसे समय आया है, जब पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच चुका है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। पीट हेगसेथ ने पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान में अब नया शासन है और उसे पहले से ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए तैयार हैं और उसकी शर्तें ईरान को पहले से पता हैं। लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान इन शर्तों को नहीं मानता, तो अमेरिकी सेना और ज्यादा ताकत के साथ हमला जारी रखेगी। हेगसेथ के मुताबिक, पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को सत्ता दी गई है। अली खामेनेई करीब चार दशकों तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। हालांकि मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं।

लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार

नईदिल्ली। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली बॉर्डर से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आतंकी शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर लश्कर का एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहा था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे राजधानी की सीमा पर दबोच लिया. जांच में पता चला है कि वह सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के अनुसार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के मिशन पर था। जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में उसके कितने और साथी छिपे हुए हैं. बीते दिनों दिल्ली और साउथ इंडिया से लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था. इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई जगह भारत विरोधी पोस्टर लगाए थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल और सेंट्रल एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. शब्बीर अहमद लोन सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई नया नाम नहीं है।

देश को नक्सल मुक्त कराया... अमित शाह का जवाब नहीं

नीरज कुमार दुबे

भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय आखिरकार समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है, जिसने छह दशकों तक देश की आंतरिक सुरक्षा को लहूलुहान किया, विकास को बंधक बनाया और अनगिनत जिंदगियों को निगल लिया। यह अध्याय है नक्सलवाद का, जिसकी शुरुआत उत्तर बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में हुई थी और जिसने धीरे धीरे पूरे देश में अपने हिंसक पंजे फैला दिए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ चलाये गए अभियानों की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा, ''हम ऐसा कह सकते हैं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं।'' उन्होंने कहा कि माओवादियों की शीर्ष इकाई और केंद्रीय ढांचा लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस तरह लाल आतंक लगभग खत्म हो चुका है और देश नक्सल मुक्त होने की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

देखा जाये तो गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद अमित शाह ने जो निर्णायक कदम उठाए, उन्होंने देश की सुरक्षा तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उन्होंने दशकों से जमे आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ पर सीधा प्रहार किया, पत्थरबाजी जैसी घटनाएं समाप्त कर दीं और वहां शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ। अब जब रेड कॉरिडोर भी समाप्ति की कगार पर है, तो यह साफ है कि अमित शाह के नेतृत्व और मोदी सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति ने देश की आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती दी है।

हम आपको याद दिला दें कि नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुई थी, जब एक किसान विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया। चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। शुरुआत में यह जमींदारों के

खिलाफ था, लेकिन जल्द ही यह एक खतरनाक विचारधारा में बदल गया जिसने युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया।

देखते ही देखते यह आग बिहार, ओडिशा, झारखंड और देश के कई हिस्सों में फैल गई थी। समय के साथ यह तथाकथित लाल गलियारा बन गया, जो कर्नाटक से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके प्रमुख केंद्र बन गए थे। कर्नाटक में भी नक्सलवाद ने तीन दशक तक आतंक फैलाया। लेकिन सख्त पुलिस कार्रवाई, आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास कार्यक्रमों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया। 2025 तक यह राज्य आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित हो गया।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कहानी और भी खतरनाक रही। यहां लैंडमाइन धमाके, पुलिस अधिकारियों की हत्या और बड़े पैमाने पर हिंसा आम बात बन गई थी। लेकिन ग्रेहाउंड बल की स्थापना, लगातार अभियान और सटीक खुफिया रणनीति ने इस नेटवर्क की कमर तोड़ दी। 2025 में शीर्ष नक्सली नेताओं के मारे जाने और आत्मसमर्पण की लहर ने इस आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया।

छत्तीसगढ़, जो कभी नक्सलवाद का सबसे बड़ा गढ़ था, वह आज विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे इलाके, जहां कभी सरकार की पहुंच नहीं थी, अब वहां सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट और बाद में ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।

बस्तर, जिसे लाल आतंक का दिल कहा जाता था, आज उस साये से बाहर निकल चुका है। अमित शाह ने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त है, वह केवल बयान नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है।

वहीं मध्य प्रदेश में हॉक फोर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई और नक्सलियों के ठिकानों को एक एक कर खत्म किया। बिहार और झारखंड, जो कभी सबसे ज्यादा प्रभावित थे, वहां भी स्थिति में भारी सुधार हुआ है। बेहतर पुलिसिंग, विकास योजनाएं और राजनीतिक इच्छाशक्ति ने इस समस्या को जड़ से कमजोर किया। केरल में भी नक्सल गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं।

एके-47 के साथ थाने पहुंचे दो नक्सली

कुल सात नक्सलियों का समर्पण

जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री की समय सीमा के अंतिम दिन 31 मार्च को कांकेर जिले में दो नक्सलियों ने समर्पण किया। इसके अतिरिक्त, दंतेवाड़ा जिले में भी पांच नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है। दंतेवाड़ा में पांच नक्सलियो ने 40 हथियार भी जमा करवाये हैं। यह घटनाक्रम बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता को दर्शाता है। कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि पिछले सात दिनों में कुल 11 नक्सली कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया था।

इसी क्रम में 31 मार्च को पीपीसीएम शंकर और पीएम हिडमा डोडी ने भी मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। शासन की पुनर्वास नीति के तहत एक कैडर ने एके 47 के साथ आत्मसमर्पण किया है। समर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि इलाके में सक्रिय अन्य नक्सली कैडरों से भी चर्चा हुई है। वे भी मुख्यधारा में शामिल होने की बात कह रहे हैं, और उन्हें लाने के प्रयास जारी हैं। पुलिस प्रशासन इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह समर्पण अभियान क्षेत्र में शांति स्थापित करने में सहायक होगा। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टलिंगम ने पिछले तीन दिनों में मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आए इन सभी 11 नक्सली कैडरों के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने शेष बचे कुछ नक्सली कैडरों से एक बार फिर हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील दोहराई। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि नक्सली कैडरों के पास आत्मसमर्पण और पुनर्वास का विकल्प चुनने के लिए अब केवल कुछ ही घंटे शेष हैं। उन्हें इस अवसर का उपयोग करके अपने हिंसक अतीत को त्यागना चाहिए। उन्हें सामान्य, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन अपनाना चाहिए। 25 मार्च से 31 मार्च तक मुख्यधारा में शामिल होने वाले इन सभी 11 नक्सली कैडरों ने पुनर्वास का मार्ग चुना है। उनकी सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की कार्रवाई पूरी प्रक्रिया होने के बाद आयोजित की जाएगी। दंतेवाड़ा में पांच नक्सलियों ने भी मुख्यधारा में शामिल होकर नक्सलियों की खोखली विचारधारा को त्याग दिया है। दो जिलों कांकेर और दंतेवाड़ा में कुल सात नक्सलियों ने सरेंडर किया।

बांस की डंडी के सहारे आता है मोबाइल नेटवर्क, 125 गांवों में समस्या, डिजिटल क्रांति के दावों पर सवाल

■ **एमसीबी क्षेत्र के भरतपुर सोनहत विधानसभा में आज भी कई गांव नेटवर्क विहीन है.इस समस्या के कारण लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं.**

कोरिया/एमसीबी। भरतपुर सोनहत विधानसभा में आज भी कई गांव मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे हैं। भले ही आज सरकार ये दावा कर रही हो कि आम जनता के काम को निपटाने के लिए डिजिटल क्रांति का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन यदि सुदूर गांवों की तस्वीर देखें तो इन दावों में हकीकत कम ही नजर आती है। कोरिया जिले का सुदूर वनांचल क्षेत्र आज भी बुनियादी मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। भरतपुर-सोनहत विधानसभा के करीब 125 गांव ऐसे हैं, जहां आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीणों को बांस की लकड़ियों से अस्थायी टावर बनाकर सिग्नल का जुगाड़ करना पड़ता है। कोरिया जिले के रामगढ़ इलाके में नेटवर्क संकट सबसे गंभीर रूप में सामने आया है। यहां करीब 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाली छह ग्राम पंचायतें रामगढ़, नटवाही, सिंघोर, दसेर, आनंदपुर और अमृतपुर पूरी तरह नेटवर्क विहीन हैं। इन गांवों में मोबाइल फोन तो लगभग हर घर में है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण फोन सिर्फ डिब्बा है। ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर जाकर या बांस के सहारे मोबाइल को ऊंचाई पर बांधकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार घंटों मशक्कत के बाद भी सिग्नल नहीं मिलता,और यदि कभी कभार सिग्नल मिल भी जाए तो ये कुछ ही मिनटों में गायब हो जाता है। भरतपुर-सोनहत विधानसभा के 403 गांवों में से करीब 125 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है। यह स्थिति न केवल विकास की गति को प्रभावित कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को मुख्यधारा से भी दूर कर रही है। हालांकि, प्रशासन द्वारा कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में लगे पुराने 2 प्रतिशत टॉवरों को 4ज में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह इस मुद्दे को विधानसभा में उठा चुकी हैं। उनके अनुसार, 85 ग्राम पंचायतों में नए टॉवर लगाने की स्वीकृति मिल चुकी है और 31 मार्च के बाद इस दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। नेटवर्क के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होता है- सुखलाल सिंह, ग्रामीण ग्रामीणों को नेटवर्क के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। किसी जरूरी कॉल, बैंकिंग या ऑनलाइन दस्तावेज के लिए ग्रामीणों को जंगल-पहाड़ पार करना पड़ता है।

मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। रायगढ़ पुलिस ने एक शातिर संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 युवक और 1 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल दुकान में चोरी और दो बैंकों में डकैती की साजिश का भी खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से 2 चार पहिया वाहन, 60 मोबाइल और अन्य सामान सहित लगभग 26 लाख 47 हजार की संपत्ति बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, गैंग के सरगना मोह। अरसलान ने अपने हमउम्र युवकों का गिरोह बनाकर घरघोड़ा, धरमजयगढ़ और जूटमिल में मोबाइल शॉप और बैंकों में चोरी-लूट की योजना बनाई थी। फरवरी और मार्च 2026 में हुए प्रयासों में कुडुमकेला की मोबाइल दुकान में चोरी, धरमजयगढ़ ग्रामीण बैंक और जूटमिल पंजाब नेशनल बैंक में नकबजनी के प्रयास शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को समय रहते रोक दिया। घटना की जांच में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की गई। आरोपियों ने रेकी करके टारगेट तय किया और सबूत मिटाने तक की योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपियों में मोह। अरसलान (19), करण महंत (30), अलतमस खान (19), जॉनसन बेक (19), कवलेश यादव (19) और एक नाबालिग बालक शामिल हैं। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया, घरघोड़ा पुलिस की टीम ने पेशेवर तरीके से इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और बैंकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे गिरोहों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

डोर-टू-डोर डिलीवरी को दें प्राथमिकता, गोदामों पर भीड़ लगाने वाली एजेंसियों पर होगी कार्यवाही: कलेक्टर

जगदलपुर। जिले के विभिन्न गैस सिलेंडर गोदामों पर उमड़ रही भीड़ और अव्यवस्था की खबरों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर आकाश छिकारा ने प्रशासनिक अमले को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल गैस गोदामों का निरीक्षण करें और जहां भी भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है, वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती कर स्थिति का जायजा लें। कलेक्टर ने कहा है कि नागरिकों को किसी भी तरह से घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी गैस एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि वे गोदामों पर भीड़ जमा करने के बजाय निर्धारित समय सीमा के भीतर डोर-टू-डोर डिलीवरी को प्राथमिकता दें। प्रशासन का मुख्य जोर इस बात पर है कि उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही सुगमता से सिलेंडर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने खाद्य विभाग और राजस्व अधिकारियों को कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखने तथा उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने विशेष रूप से ओवररेटिंग की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि यदि कोई गैस एजेंसी अतिरिक्त राशि लेकर प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर प्रदान करती पाई जाती है, तो उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिलेंडर वितरण में पारदर्शिता अनिवार्य है और किसी भी स्तर पर उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

म्युल अकाउंट के जरिए ठगने वाले 10 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में म्युल अकाउंट के माध्यम से सायबर ठगी से अर्जित पैसों को अपने खातों में ट्रांसफर कराने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सभी आरोपियों के अकाउंट से 83 लाख 33 हजार 247 रुपए की अवैध राशि खातों में ट्रांसफर कर लेनदेन की जानकारी मिली है। दरअसल पुलिस को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल द्वारा कर्नाटक बैंक दुर्ग में संचालित बैंक खातों का विश्लेषण किया गया तो जांच में पाया गया कि इन खातों का उपयोग देश के विभिन्न स्थानों से साइबर ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। कुल लगभग 86 लाख 33 हजार 247 रुपए का अवैध लेन-देन भी पाया गया।

इसके बाद पुलिस ने तत्काल बैंक से संपर्क करते हुए सभी खातों को होल्ड कर विवेचना शुरू की तो शिकायत सही पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी दस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि म्युल अकाउंट वे बैंक के खाते होते हैं, जिसे संबंधित खाताधारक साइबर ठगी के रुपए के ट्रांसफर के लिए और ऑनलाइन बेटिंग में उपयोग करने के लिए किराए पर देते हैं। किराए पर दिए गए इस म्युल अकाउंट के बदले में बाकायदा खाताधारकों को हर माह किराए की एकमुश्त राशि भी दी जाती है। फिलहाल दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह के म्युल अकाउंट पर कार्रवाई कर रही है।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : ढाई दशक पुराने फर्जी वेतन घोटाले में सभी आरोपी बरी

कोर्ट ने कहा : सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा

बिलासपुर। जगदलपुर के ढाई दशक पुराने बहुचर्चित फर्जी वेतन आहरण और भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा। मामला जगदलपुर स्थित स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1979 से 1985 के बीच कथित रूप से फर्जी वेतन बिल बनाकर सरकारी राशि निकालने से जुड़ा था, जिसमें करीब 42 हजार रुपये के गबन का आरोप था। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके सेन और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर आरोप था कि उन्होंने मिलकर तीन सफाई कर्मचारी जयसिंह, लालमणि और मयाराम के नाम पर फर्जी वेतन बिल तैयार किए। कहा गया कि ये कर्मचारी वास्तविक रूप से काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके नाम पर वेतन निकालकर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। आरोप यह भी था कि वेतन बिलों में फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए गए। जगदलपुर की विशेष अदालत ने 28 जनवरी 2002 को इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) और 120-बी (साजिश) सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2-2 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामले में गवाहों के बयान से यह सामने आया कि सभी कार्य तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. आरके सेन के निर्देश पर किए गए थे। कोर्ट ने माना कि अन्य आरोपी केवल अधीनस्थ कर्मचारी थे, जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई स्वतंत्र भूमिका या आपराधिक मंशा साबित नहीं हुई। उन्होंने केवल अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया, जिसे अपराध नहीं माना जा सकता। मामले में जिन कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाले जाने का आरोप था, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वे कब तक काम पर नहीं थे या उन्हें वेतन नहीं मिला। कई गवाहों ने कहा कि उन्हें काम के दौरान वेतन मिला और उन्होंने हस्ताक्षर कर भुगतान लिया। इससे अभियोजन का दावा कमजोर हो गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की गहन समीक्षा के बाद पाया कि अभियोजन के पास आरोप साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। किसी भी आरोपी के खिलाफ यह साबित नहीं हुआ कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए या उनका उपयोग किया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भिलाई आत्महत्या मामला कांग्रेसी नेता गिरफ्तार

दुर्ग। भिलाई के कोहका स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुए मोहन रामटेके आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेसी नेता राजू पाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने इलाके में काफी चर्चा और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि 28 मार्च को कोहका निवासी मोहन कुमार रामटेके 42 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर में मिला था। शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया। सुसाइड नोट में मोहन ने अपनी मौत के लिए राजू पाल और सोनिया गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया। सीएसपी ने बताया कि मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा था कि राजू पाल और सोनिया गोस्वामी से उसने उधार में रुपये लिए थे। रुपये वापस देने को लेकर दोनों आरोपी उसे लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिससे वह तनाव में आ गया था। पुलिस ने इस आधार पर दोनों के खिलाफ स्मृति नगर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

प्रॉपटी हड़पने भाई की हत्या की 15 आरोपी हुए गिरफ्तार

मुंगेली। मुंगेली जिले में संपत्ति हड़पने के इरादे से छोटे भाई ने सुपारी देकर बड़े भाई की हत्या की साजिश रच मौत के घाट उतारा। दामोदर सिंह (62) रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी थे। उनके पास लगभग 4 करोड़ की प्रॉपटी और 30 तोला सोना था, जो कि उसके छोटे भाई हड़पना चाहता था। मर्डर के लिए उसने गांव के ही युवक से 10 लाख रुपए और 50 डिसमिल जमीन देने की डील की थी और साढ़े 4 लाख रुपए एडवांस भी दे भी दिए थे। मामला लालपुर थाना क्षेत्र का है। वारदात में 15 लोग शामिल थे। 21 मार्च को दामोदर को बुलाकर गमछे से उसका गला घोंटा गया, लाश घटनास्थल से 60 किमी दूर जंगल ले जाकर रेत में दफनाया गया, फिर मोबाइल नदी में बहा दिया था। 8 दिन बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पूर्व कांग्रेस नेता समेत 4 नाबालिग और परिवार के ही सदस्य है।दरअसल, दामोदर सिंह राजपूत (62) शिक्षा विभाग में लेखा अधिकारी थे। जो रिटायर के बाद मुंगेली में किराए के मकान में रह रहे थे।

हाईकोर्ट: घर में प्रेयर, मीटिंग करने वालों को परेशान न करें

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर विवाद के बीच अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रार्थना सभा के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी नहीं है। सिंगल बेंच ने इस आदेश में पुलिस की ओर से जारी नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना सभा रोकने के लिए बार-बार नोटिस दे रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। यह मामला जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधना से जुड़ा है। दरअसल, ग्राम गोधना में याचिकाकर्ताओं ने अपने आवास की पहली मंजिल पर हॉल बनाया है। इसके बाद से 2016 से यहां ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इन सभाओं में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती।

सर्किट हाउस में एंट्री रोकी तो भड़कीं बीजेपी नेत्री

बिलासपुर। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दौरे के दौरान भाजपा नेत्री गौरी गुप्ता का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल, गौरी गुप्ता सर्किट हाउस जाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इससे भाजपा नेत्री जमकर भड़क गई। गौरी गुप्ता कहने लगी कि एसपी से बात कराना, एसपी कभी नहीं रोकता। प्रोटोकॉल नहीं पता है क्या इन लोगों को। हमारे ही सीएम हैं वो समझे। भाजपा नेत्री की इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, बहस के बीच एक बीजेपी नेता के दखल के बाद उन्हें अंदर एंट्री मिल गई। हंगामे के बीच एक भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, जिनके हस्तक्षेप के बाद गौरी गुप्ता को सर्किट हाउस के अंदर एंट्री मिलीई। हंगामे के बीच एक भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, जिनके हस्तक्षेप के बाद गौरी गुप्ता को सर्किट हाउस के अंदर एंट्री मिल गई। दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर दौरे पर थे। रिवर व्यू में भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल विहारी वाजपेयी की प्रतिमा अनावरण के बाद सीएम सर्किट हाउस पहुंचे।

दुर्ग के सब्जी मंडी में नशीली दवाएं बेचते युवक गिरफ्तार

दुर्ग-भिलाई। जिले के मोहन नगर थाना पुलिस ने धमधा रोड स्थित सब्जी मंडी में घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रतिबंधित नशीली दवाओं बेचने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से 72 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। यह कार्रवाई 29 मार्च को की गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धमधा रोड स्थित सब्जी मंडी के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूम रहा है और उसके पास नशीली दवाएं हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की और संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।पुलिस टीम ने जब युवक की तलाशी ली, तो उसके पहने हुए लोवर की जेब से प्रतिबंधित नशीली दवाओं के 72 कैप्सूल बरामद किए गए। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय दीपक ठाकुर के रूप में हुई है, जो दुर्ग के सिकोला भाठा इलाके का निवासी है।कड़ाई से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह इन दवाओं को अवैध रूप से बेचने का काम कर रहा था।

नक्सलवाद मुक्त भारत की डेडलाइन पूरी, ख्वाब अधूरी, अब अर्बन नक्सलियों पर नजर

कमलेश पांडे

आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियां बनी हुई हैं। फरवरी 2026 तक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6-7 रह गई थी, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर) में। वहीं, मार्च 2026 के अंत में सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई, जहाँ एक नक्सली मारा गया। देश के पीएम इन वेटिंग और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों और आतंकवादियों की कमर तोड़ने में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भारत अभी पूरी तरह नक्सलवाद और आतंकवाद मुक्त हुआ है। हां, सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं। यदि शाह अपने नेक मकसद में कामयाब हुए तो प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मनमाफिक राष्ट्रीय टीम पहले से ही बना रखी है।

यह ठीक है कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, और

आतंकवाद समाप्ति को लेकर ऐसा कोई दुरूह लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था और कड़ी कार्रवाई गतिमान है, लेकिन पूरे देश की बात छोड़ दी जाए तो खुद दिल्ली-एनसीआर से ब्रेक के बाद सामने आने वाले मामले इस बात की चुगली कर रहे हैं कि उद्देश्यपूर्ति काफी जटिल है। ऐसा इसलिए कि नक्सलियों और आतंकवादियों को बौद्धिक और आर्थिक खुराक देने वाली जमात राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हलकों में सक्रिय हैं! प्रशासनिक गलियारों तक में इनकी जातिवादी और सांप्रदायिक पैठ है। जबतक इनकी शिनाख्त और गिरफ्तारी नहीं होती, उद्देश्य अधूरा रहेगा। संभव हो कुछ तत्व सत्ताधारी दल से भी डायरेक्ट या भाया मीडिया सम्बन्धित हों। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियाँ बनी हुई हैं। फरवरी 2026 तक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6-7 रह गई थी, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर) में। वहीं, मार्च 2026 के अंत में सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई, जहाँ एक नक्सली मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि नक्सलवाद लगभग समाप्ति की कगार पर है, लेकिन औपचारिक घोषणा प्रक्रिया पूरी होने पर होगी। सरकारी दावा करते हुए अमित शाह ने 30 मार्च को लोकसभा में कहा कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है और नक्सलवाद विलुप्ति की ओर है। 31 मार्च की डेडलाइन के ठीक पहले भी ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें सैकड़ों नक्सली मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फिर भी, बस्तर जैसे क्षेत्रों में सीमित गतिविधियाँ जारी हैं। प्रगति के आंकड़े बताते हैं कि नक्सल प्रभावित जिले 126 (2010) से घटकर 6-7 (2026) पर पहुंच गए और ज्यादातर नक्सली मारे गए। 700+ तो हाल के वर्षों में।वहीं, आत्मसमर्पण करने वाले 4,800+ नक्सली दूसरे धंधों में जुड़ चुके हैं। बहरहाल, नक्सलवाद बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन पूर्ण मुक्ति की घोषणा अभी बाकी है। भारत में नक्सल प्रभावित 6 जिलों की स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है, जहाँ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। ये जिले मुख्यत: छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रित हैं। वहीं, सबसे अधिक प्रभावित जिले निम्नलिखित 6 जिले हैं, जिनके नाम छत्तीसगढ़ (बीजापुर, कांकेर/नारायणपुर, नारायणपुर, सुकमा), झारखंड (पश्चिमी सिंहभूम), और महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) हैं। इनमें नक्सली गतिविधियां सीमित लेकिन सक्रिय हैं, जैसे छिपे हुए कैंप और छोटे हमले। सुरक्षा बलों ने हाल के ऑपरेशनों से इन क्षेत्रों में घुसपैठ बढ़ाई है। जहां तक वर्तमान अभियान की बात है तो छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद (कभी-कभी सूचीबद्ध) में हाई-अलर्ट सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सरकार ने अंतिम बड़े अभियान की तैयारी की है, जिसमें आत्मसमर्पण और मुठभेड़ों पर जोर है। मार्च 2026 तक हिंसा में भारी कमी आई, लेकिन पूर्ण नियंत्रण बाकी है।वहीं प्रगति संकेत यह है कि नक्सली संख्या घटी, सैकड़ों आत्मसमर्पण हुए। विकास परियोजनाएँ शुरू हुईं, जैसे सड़कें और स्कूल। फिर भी, जंगलों में छिटपुट गतिविधियाँ जारी हैं। लिहाजा, 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद भी इन जिलों पर फोकस रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित 6 जिलों (मुख्यत: छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर/नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरोली) को नक्सल मुक्त करने के लिए बहुआया रणनीति अपनाई है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य रखती है, जिसमें सुरक्षा अभियान, आत्मसमर्पण नीति और विकास पर जोर है। सुरक्षा अभियान भी जारी है।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल रमेन डेका से रेडियो संगवारी टीम ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से मंगलवार

को लोक भवन में रेडियो संगवारी की टीम ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान टीम ने रेडियो संगवारी की परिकल्पना, उद्देश्यों तथा आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।टीम के संस्थापक श्री राहुल शर्मा ने बताया कि रेडियो संगवारी टीम द्वारा प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है और ऐसे प्रयास इसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने रेडियो संगवारी टीम को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस अवसर पर रेडियो संगवारी टीम के डॉ. हेमंत सिरमौर, सुश्री श्रीया सिरमौर, श्री शिवनंदन सरोज, तिलका साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

होलीक्रॉस के दो स्कूल सील, बकाया टैक्स नहीं पटाने पर निगम ने की कार्रवाई

रायपुर। राजधानी रायपुर में नगर निगम ने

टैक्स बकाया होने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए होलीक्रॉस के दो स्कूलों को सील कर दिया है। नगर निगम जोन क्रमांक 4 के राजस्व विभाग ने आयुक्त के सख्त निर्देश पर यह कार्रवाई की। नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने बताया, होलीक्रॉस स्कूल बैरनबाजार पर लगभग 34 लाख रुपये का टैक्स बकाया था, जबकि होलीक्रॉस स्कूल शैलेन्द्र नगर पर करीब 24 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। बार-बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर निगम की टीम ने दोनों स्कूलों में ताला लगाकर उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही होलीक्रॉस स्कूल कांपा प्रबंधन ने सक्रियता दिखाते हुए अपना पूरा बकाया तुरंत नगर निगम को जमा कर दिया, जिससे उस पर सीलिंग की कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप का कहना है कि बकायेदारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दनौट कया-कमतरा सड़क के लिए 18.72 करोड़ रुपए मंजूर

रायपुर। राज्य शासन ने रायगढ़ जिले में दनौट कया-कमतरा मार्ग के उन्नयन के लिए 18 करोड़ 71 लाख 96 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 13.4 किमी सड़क के उन्नयन के साथ ही 60 मीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं।

संपत्ति कर जमा करने की तारीख अब 30 अप्रैल तक बढ़ी

रायपुर। संपत्ति कर(प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगरीय प्रशासन-विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है, जो पहले 31 मार्च थी। विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके बाद भुगतान करने पर 17 प्रश सरचार्ज देना होगा।

ईओडब्ल्यू ने पीसीसी कार्यालय के 4 कर्मचारियों को किया तलब

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेशण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ब्यूरो ने शिशुपाल साहू, सोहन, गजेंद्र यादव, रूपेंद्र को समन किया है। इनसे पार्टी फडिंग को लेकर पूछताछ की जानी है।

मुख्यमंत्री साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी

300 बीएलएस, 70 एएलएस के साथ पहली बार 5 नियोनेटल एएलएस — नवजात शिशुओं के लिए 'चलते-फिरते आईसीयू' की शुरुआत

रायपुर। प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एवं 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की समस्त सेवाएं प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गई हैं, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता सुनिश्चित होगी।

इस पहल के अंतर्गत पहली बार प्रदेश में 5 नियोनेटल एएलएस एम्बुलेंसों की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं की आपातकालीन देखभाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह सेवा राज्य की नवजात सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा गंभीर स्थिति में नवजात शिशुओं को सुरक्षित रूप से उच्च स्तरीय उपचार केंद्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुदृढ़ हो रही हैं और पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का भरोसा सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ा है, जहां उन्हें

समय पर उपचार मिल रहा है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन के कारण अब लोगों को छोटे-छोटे इलाज के लिए दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर जरूरतमंद मरीज तक समय पर स्वास्थ्य सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा का यह विस्तार आम जनता के विश्वास को और सशक्त करेगा कि संकट की घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहली बार शुरू की गई 5 नियोनेटल एएलएस एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक है और इससे लाखों लोगों को त्वरित चिकित्सा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एम्बुलेंस सेवा में किसी भी प्रकार की देरी या कमी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है।

प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक समय पर सहायता पहुंच सके।

नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इनमें प्रशिक्षित नवजात इमरजेंसी तकनीशियन, 24×7 ईएमटी एवं पायलट की उपलब्धता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का ऑनलाइन मार्गदर्शन सुनिश्चित किया गया है। इन एम्बुलेंसों में इन्क्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, नेब्युलाइज़र, सक्शन मशीन, पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं 41 प्रकार की आपातकालीन दवाओं सहित सभी आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इन्हें चलते-फिरते नवजात आईसीयू के रूप में स्थापित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएलएस एवं एएलएस एम्बुलेंसों में मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक एवं उन्नत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जैसी जांच सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट, नेब्युलाइजेशन एवं अन्य आपातकालीन उपचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गंभीर मरीजों के सुरक्षित स्थानांतरण हेतु पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर मॉनिटर, सिरिंज पंप, लैरिंजोस्कोप सहित अन्य उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह समग्र पहल प्रदेश के शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के लिए एक मजबूत जीवनरक्षक तंत्र के रूप में स्थापित होगी।

इस अवसर पर विधायक श्री मोती लाल साहू, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री संजीव झा, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री रणबीर शर्मा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्री रितेश अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नक्सलवाद पर सियासत: भूपेश ने अमित शाह को बहस की दी चुनौती

सीएम साय बोले- नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प पूरा, अब तेजी से बस्तर का होगा विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को नक्सलवाद के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी है। बघेल ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सल समस्या को खत्म करने केंद्र की भाजपा सरकार को पूरा सहयोग किया गया था, लेकिन अमित शाह ने संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान यह झूठ कहा कि कोई सहयोग नहीं किया था। सच्चाई यो यह है कि मदद भी किया गया था। साथ नक्सल मोर्चे पर जोखिम लेकर हमारी सरकार ने विकास के अनेक कार्य किए थे।

वहीं नक्सलवाद को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज 31 मार्च का ये दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे जवानों के साहस से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा बाधक था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था और उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब

बस्तर क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा।

नक्सलवाद और कांग्रेस के आरोपों पर सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल ने जो कहा है वह असत्य है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। दिसंबर 2023 में सरकार आने के बाद अगले ही महीने नक्सल प्रभावित प्रदेश की समीक्षा हुई और उसमें पता चला कि 75 फीसदी नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में है। अपने 5 साल के कार्यकाल में तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार माओवाद के साथ लड़ने में दृढ़ता प्रकट की होती, ठीक नियत से लड़ी होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रदेश शासन का सहयोग केंद्र सरकार को नहीं मिला और आज अगर भूपेश बघेल इस तरह से बोलते हैं तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं।

झीरम घाटी कांड की न जांच कराए न ही जेब वाला सबूत निकला : मुख्यमंत्री

झीरम के सबूत को लेकर सीएम साय ने कहा कि डॉ. रमन सिंह की जब सरकार थी तो वो नेता प्रतिपक्ष थे तो कहते थे झीरम घाटी का सबूत हमारे जेब में है। सरकार में ना तो वह झीरम घाटी की जांच करवा पाए न ही जेब वाला सबूत निकला। राहुल गांधी ने जो देश जोड़ो यात्रा निकाली थी उस दरमियान उन्होंने अनेकों जगह जो नक्सली थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। कई जगह नक्सलियों ने उनके साथ मंच साझा किया। जब हिडमा जैसा दुर्दांत नक्सली न्यूट्रिलाइज़ हुआ। जिसने सैंकड़ों लोगों को मारा, जिसमें हमारे जवान भी थे और जब वो स्वयं न्यूट्रिलाइज़ हुआ तो इंडिया गेट के पास कितने हिडमा मारोगे, घर-घर में हिडमा पैदा होंगे। ऐसा लोगों के द्वारा नारा लगाया गया और उसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो ये क्या प्रमाणित करता है। देश जानता है कि इसके पीछे राहुल गांधी का क्या आशय है।

बीएसएनएल के सिम की सुविधा अब डाकघरों में भी

रायपुर। इंडियन पोस्ट के अंतर्गत रायपुर के मुख्य डाकघर रायपुर में भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की सेवाओं उदघाटन किया गया।अब रायपुर जीपीओ में डाक सेवाओं के साथ-साथ बीएसएनएल के सिम कार्ड भी उपलब्ध रहेंगे।इस सेवा के माध्यम से नागरिकों को बीएसएनएल के नए प्रीपेड सिम कार्ड, एवं बीएसएनएल मोबाइल सिम रिचार्ज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें डाक विभाग एवं बीएसएनएल मिलकर देश के हर नागरिक तक संचार सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करेंगे।रायपुर जीपीओ में बीएसएनएल सिम से संबंधित सुविधाएं मिलने से नागरिकों को बेहतर, सुलभ एवं एकीकृत सेवाएं प्राप्त होंगी, जिससे जनसुविधा एवं डिजिटल सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। इस सुविधा का शुभारंभ माननीय निदेशक डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ परिमंडल श्री दिनेश कुमार मिस्त्री के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बी एस एन एल रायपुर के डीजीएम श्री वाई पी सिंह, एवं एजीएम श्री मिलिंद उपासनी एवं प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री एच.के.महावर तथा डाक विभाग व बीएसएनएल के अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

कप्तान किरण ने छत्तीसगढ़ को फुटबॉल फाइनल में पहुंचाया

रायपुर। कप्तान किरण पिस्दा की शानदार दोहरी भूमिका से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के फाइनल में जगह बना ली है, जबकि राज्य की महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक मुकाबले में पहुंचकर अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किरण ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद कोटा स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच की स्टार रहीं। उनके हरफनमौला खेल की बदौलत छत्तीसगढ़ ने निर्धारित समय के बाद 2-2 की बराबरी रहने पर पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से रोमांचक जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में अब तक करीब 20 गोल कर चुकीं किरण ने एक बार फिर आक्रामक भूमिका निभाते हुए 18वें मिनट में गोल कर मेजबान टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई।

हालांकि अरुणाचल प्रदेश ने 41वें और 86वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और मैच को शूटआउट में पहुंचा दिया। इसके बाद किरण ने साहसिक फैसला लेते हुए नियमित गोलकीपर योगिता की जगह खुद दस्ताने पहनकर गोलपोस्ट संभालने का निर्णय लिया। उनका यह निर्णय कप्तानी की मिसाल बन गया, जब उन्होंने दो शानदार बचाव किए और खुद एक पेनल्टी भी सफलतापूर्वक गोल में बदली, जिससे टीम को फाइनल का टिकट मिला। अंतिम पेनल्टी के गोल के साथ ही मेजबान टीम ने मैदान पर जश्न मनाना शुरू कर दिया।

अपने प्रदर्शन पर किरण ने साई मीडिया से कहा, मैं अपनी टीम को हर हाल में फाइनल में पहुंचाना चाहती थी। मुझे गोलकीपर के रूप में अच्छा करने का भरोसा था। मैंने पहले भी अपनी राज्य टीम के लिए यह भूमिका निभाई है। मेरी मेहनत सफल रही और हम फाइनल में हैं। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। अब फाइनल में छत्तीसगढ़ का सामना झारखंड और गुजरात के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। उल्लेखनीय है कि ग्रुप चरण में मेजबान टीम गुजरात को 2-1 से हरा चुकी है, जिसमें किरण ने भी एक गोल किया था।

भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव पर निकली शोभायात्रा

रायपुर। राजधानी रायपुर समेत प्रदेशभर में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। शहर में पूर्व मंत्री राजेश मूणत के मार्गदर्शन में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।

यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दादाबाड़ी तीर्थ पहुंची। जहां सुबह 10 बजे से भगवान महावीर पंचकल्याणक पूजा, महा रक्तदान शिविर और साधर्मिक वात्सल्य जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद

पारंपरिक तरीके से वरघोड़ा वापसी निकाली गई, जिसमें समाजजनों की भारी उपस्थिति देखने को मिली और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

महोत्सव समिति, समता युवा संघ और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से हुए इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रेश शाह ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर आयोजित की गई।

छग दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कांवड़िया ने कहा कि भगवान महावीर का यह 2625वां जन्मदिवस है। हर वर्ष भव्यता के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रायपुर में यह महोत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता सहित विभिन्न आयोजन किए जाते हैं।

नक्सलवाद की पोषक तो भाजपा की नीतियां थी : कांग्रेस

रमन राज के 15 सालों में नक्सलवाद 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक पहुंच गया था

रायपुर। भाजपा द्वारा नक्सल मामला पर अपनी पीठ थपथपाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद भाजपा के रमन सरकार के समय पूरे प्रदेश फैला जब राज्य में 2003 में भाजपा की सरकार बनी तब नक्सलवाद बस्तर के 3 ब्लॉकों तक ही सीमित था। रमन राज के 15 सालों में नक्सलवाद बस्तर के तीन ब्लॉकों से निकलकर 14 जिलों तक पहुंच गया। इन 15 सालों के अंत के 4 साल तक केंद्र में नरेन्द्र मोदी की भी सरकार बन चुकी थी। प्रधानमंत्री इस तथ्य को जान ले राज्य में नक्सलवाद की जिम्मेदार भाजपा की फासीवादी सोच और नीतियां है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियों में 80 प्रतिशत की

कमी हुई थी। नक्सलियों के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर हुआ है, तब नक्सली छत्तीसगढ़ छोड़कर भाग गये थे। वर्ष 2008 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो इस दौरान राज्य में नक्सली हर साल 500 से लेकर 600 हिंसक घटनाओं को अंजाम देते थे, जो भूपेश सरकार के 5 सालों में घटकर औसतन रूप से 250 तक रह गई थी। वर्ष 2023 में मात्र 134 नक्सल घटनाएं हुई हैं, जो कि 2018 से पूर्व घटित घटनाओं से लगभग चार गुना कम थी।

राज्य में 2018 से पूर्व नक्सली मुठभेड़ के मामले प्रतिवर्ष 200 के करीब हुआ करते थे, जो भूपेश सरकार में घटकर दहाई के आंकड़े तक सिमट गए हैं। वर्ष 2021 में राज्य में मुठभेड़ के मात्र 81 और वर्ष 2023 में अब तक 41 मामले हुए थे। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामलों में भी तेजी कांग्रेस सरकार में आई थी। 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह आंकड़ा 10 वर्षों में समर्पित कुल नक्सलियों की संख्या के एक तिहाई से अधिक थी। कांग्रेस सरकार के समय बस्तर संभाग के 589 गांवों के पौने छह लाख ग्रामीण नक्सलियों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। इनमें सर्वाधिक 121 गांव सुकमा जिले के हैं। दंतेवाड़ा जिले के 118 गांव, बीजापुर जिले के 115 गांव, बस्तर के 63 गांव, कांकेर के 92 गांव, नारायणपुर के 48 गांव और कोंडागांव के 32 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री नक्सल नियंत्रण पर जो अपनी पीठ थपथपा रहे है, उसके पीछे कांग्रेस की सरकार की कार्ययोजना और बनायी गयी नीतियां है। भूपेश सरकार ने विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूलमंत्र को लेकर जो कदम उठाया। बस्तर के आम लोगों का विश्वास कांग्रेस की सरकार ने जीता था, दूरस्थ इलाकों में सुरक्षा बलो के कैंप बनाए गए, सड़क, पुलिया बनाए गए, अस्पताल, स्कूल बनाए गए, वनोपजों के वैल्यू एडिशन के रोजगार के अवसर बढ़ाए गए थे तब आज सुरक्षा बलो को सफलता मिल रही है।

2 अप्रैल से नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आगरा में

रायपुर। आगरा में 2 से 4 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए छग पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा से 52 खिलाड़ी आज ट्रेन से रवाना होंगे। जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अधिक से अधिक मेडल छग के लिए लाने की बधाई दी।

पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव मानिक ताम्रकार ने बताया कि टीम में रोहन तिवारी, जय नारायण अग्रवाल, प्रतीक चंद्राकर, सत्यजीत पृष्टि, भास्कर साहू, देवेंद्र चोरका, मुनींद्र साहू, नीतेश्वर तराम, रॉबिन चौहान, यस वर्धन सोनी, आशीष निषाद, भूमि नेभवानी, यस राजपूत, हर्ष बैरागी, विनय वैष्णव, संदीप जायसवाल, शुभम वैष्णव, संतोष बंधाते, श्रीकांत अड़े, मंजू इंगले, नवीन चंद्र कपूर, कमला देवी मांगतानी,

दिव्यांग खिलाड़ी में किशन लाल, साहिल, उदय कुमार, ललित कुमार ठाकुर, दुष्यंत ध्रुव, एलन बांसोड, किशन कश्यप, भूपेंद्र राजपूत, हरि सोनवानी, देव सिंह अहीरे, राजेंद्र ग़ेहानी, किशोर साहू, अजय ओगरे, विजय कुमार कौशिक, मुकेश लहरें, दिलदार सिंह कवर, जीवन लाल राठिया, अशोक कुमार पटेल, गोस्वामी, ब्रिज नंद पैकरा, सुंदर कुशराम, चंद्रपाल मानिकपूरी, बजरंग पटेल, टीकम सिंह सोरी, हरीश कुमार, तोरण सिंह, छोटी मेहरा, मनीषा, चतुर दास सोनवानी शामिल है। इसके अलावा दिव्यांग खिलाड़ी के कोच एवं मैनेजर किशन लाल एवं महिला पुरुष खिलाड़ी के कोच मुनींद्र साहू होंगे।

नीतीश के साथ ही नितिन ने भी छोड़ी बिहार की राजनीति

नीरज कुमार दुबे

बिहार की राजनीति में सोमवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनका यह कदम संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। इस फैसले ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को और तेज कर दिया है और माना जा रहा है कि राज्य में अब नए दौर की शुरुआत होने वाली है। नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। संविधान के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने छह महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार का इस्तीफा तत्काल सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं देता, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि वे धीरे धीरे राज्य की राजनीति से दूरी बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनका इस्तीफा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वीकार कर लिया। बताया गया कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य संजय कुमार सिंह द्वारा नीतीश कुमार का इस्तीफा पत्र सौंपा गया था। यह कदम उन नियमों के अनुरूप है जिनके तहत संसद सदस्य बनने पर राज्य विधानमंडल की सदस्यता छोड़नी होती है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना केवल पद परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक युग के समाप्त होने का संकेत माना जा रहा है। दो दशकों से अधिक समय तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहने वाले कुमार अब वापस राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि वह हमेशा से राज्य विधानमंडल और संसद के दोनों सदनों में सेवा करना चाहते थे। पिछले महीने पांच मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का संकेत देते हुए राज्यसभा जाने का निर्णय सार्वजनिक किया था। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान मिले जनसमर्थन के लिए जनता का आभार जताया और कहा कि उनकी सरकार ने विकास और सम्मान दिलाने का प्रयास किया। नीतीश कुमार के इस कदम के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद भाजपा मजबूत स्थिति में है और पहली बार राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इस बदलाव के साथ ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दशकों पुरानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का अध्याय भी लगभग समाप्त होता दिख रहा है। लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर हैं, जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा बने हुए हैं। इसी बीच, एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बांकीपुर सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भावुक संदेश के जरिए अपने समर्थकों को इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई भूमिका की शुरुआत है। नितिन नबीन ने अपने दो दशक लंबे राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि कैसे वर्ष 2006 में पहली बार विधायक बनने के बाद उन्होंने लगातार पांच बार जनता का विश्वास जीता। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को उठाने को अपनी प्राथमिकता बताया। नितिन नबीन के इस्तीफे से अब यह भी साफ हो गया है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले उन्हें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना था, लेकिन इस्तीफे में हुई देरी के कारण यह अटकलें लग रही थीं कि उन्हें राज्य की कमान सौंपी जा सकती है। अब उनके राज्यसभा जाने के साथ यह संभावना पूरी तरह समाप्त हो गई है।

माओवादी मुक्ति से शांति की नई संभावनाएं

ललित गर्ग

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा से बहुआयामी रही हैं। इन चुनौतियों में नक्सलवाद या माओवादी हिंसा एक ऐसी समस्या रही, जिसने दशकों तक देश की आंतरिक शांति, विकास और सुशासन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों ने न केवल विकास को अवरुद्ध किया, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान भी ली। लेकिन आज जब बस्तर जैसे माओवादी गढ़ से 25 लाख के इनामी सरगना पापा राव का अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण करना एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत माओवादी मुक्ति की ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानता, उपेक्षा और शोषण में रही हैं, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटककर एक हिंसक और विध्वंसकारी विचारधारा में बदल गया। माओवादी संगठन न केवल विकास कार्यों में बाधा डालते रहे, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भय और हिंसा के माध्यम से नियंत्रित किया। स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना उनकी रणनीति का हिस्सा बन गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह आंदोलन अब जनहित का नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन चुका है।

भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद/माओवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह अब लगभग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक माओवादियों के आत्मसमर्पण, सुरक्षा बलों की आक्रामक एवं रणनीतिक कार्रवाई तथा प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से हुए विकास कार्यों ने माओवादी आंदोलन की जड़ों को कमजोर कर दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में माओवादी हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व के आत्मसमर्पण, जैसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के सरेंडर ने संगठन को नेतृत्वहीन कर दिया, जिससे माओवादी संरचना भीतर से कमजोर पड़ गई। इस सफलता के पीछे सरकार की बहुआयामी रणनीति रही, जिसमें केवल सैन्य-पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि विकास, पुनर्वास और प्रशासनिक पहुंच को भी समान महत्व दिया गया। रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों के माध्यम से 4जी नेटवर्क का विस्तार, स्कूलों और आईटीआई संस्थानों की स्थापना ने इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा। वहीं 'फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों' की रणनीति के माध्यम से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के गढ़ों में घुसकर निर्णायक कार्रवाई की। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और समाज में पुनर्स्थापना की व्यवस्था ने भी माओवादी कैडर को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह समन्वित रणनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि देश आज नक्सलवाद के अंत के ऐतिहासिक चरण के निकट खड़ा दिखाई दे रहा है।

निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी और दृढ़ रणनीति अपनाई। गृहमंत्री अमित शाह की सूझबूझ और स्पष्ट दृष्टिकोण ने इस अभियान को एक नई दिशा दी। सरकार ने एक ओर जहां सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त किया, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को भी गति दी। 'सुरक्षा और विकास' के इस दोहरे दृष्टिकोण ने माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए सघन अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को गहराई से कमजोर किया है। बस्तर, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां आज आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ रही हैं। पापा राव जैसे शीर्ष माओवादी नेता का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि माओवादी संगठन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक विचारधारा के पतन का प्रतीक है।

माओवादी मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश के उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित होगी, जो लंबे समय से हिंसा की चपेट में रहे हैं। जब बंदूकें खामोश होंगी, तब विकास की आवाज बुलंद होगी। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का संचार होगा। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, जो अब तक भय और असुरक्षा में जी रहे थे, वे अब अपने अधिकारों और अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, माओवादी हिंसा के समाप्त होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। जब देश के भीतर शांति होगी, तब ही बाहरी खतरों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। नक्सलवाद जैसी समस्याएं अक्सर विदेशी शक्तियों और असामाजिक तत्वों के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं, जिन्हें समाप्त करना राष्ट्रीय हित में अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से माओवादी मुक्ति न केवल आंतरिक, बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की समान पहुंच आवश्यक होती है। माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में इन सभी तत्वों का अभाव था। वहां प्रशासन की पहुंच सीमित थी और लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही थीं। लेकिन अब जब माओवादी प्रभाव घट रहा है, तब सरकार के लिए यह अवसर है कि वह इन क्षेत्रों में सुशासन की मजबूत नींव रखे। पंचायतों को सशक्त किया जाए, स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाए और जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। यह भी आवश्यक है कि माओवादी विचारधारा के प्रभाव को केवल सुरक्षा उपायों से ही नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी चुनौती दी जाए। शिक्षा, जागरूकता और संवाद के माध्यम से लोगों को यह समझाना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। लोकतंत्र में परिवर्तन का मार्ग शांतिपूर्ण और संवैधानिक होता है। इस दिशा में समाज, सरकार और नागरिक संगठनों को मिलकर प्रयास करना होगा। माओवादी मुक्ति के इस दौर में यह भी ध्यान रखना होगा कि जिन कारणों से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, वे दोबारा न उभरें। सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और विकास की समावेशी नीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों का सम्मान करते हुए विकास की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। केवल भौतिक विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस दृढ़ता और दूरदर्शिता के साथ माओवादी समस्या का समाधान किया जा रहा है, वह न केवल वर्तमान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक है। यह दिखाता है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, रणनीति स्पष्ट हो और कार्यान्वयन प्रभावी हो, तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। निश्चिततौर पर माओवादी मुक्ति केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र, विकास और सुशासन की जीत है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि भारत अपने आंतरिक संघर्षों को शांतिपूर्ण और निर्णायक ढंग से सुलझाने में सक्षम है। अब समय है कि इस उपलब्धि को स्थायी बनाया जाए और देश के हर कोने में शांति, समृद्धि और संतुलन का वातावरण स्थापित किया जाए। जब हर नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करेगा, तभी सच्चे अर्थों में एक आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण संभव हो सकेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसके अतिरिक्त घ भाग निर्दिष्ट- सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्तात् (अथर्व 11।2।17) आदि प्रमाण से इन्द्र का सहस्राक्ष होना सुस्पष्ट है। अन्यान्य सभी आर्ष्यग्रन्थों में भी सहस्राक्ष शब्द, इन्द्र का अन्यतम पर्याय माना जाता है, परन्तु वह देवराज सहस्राक्ष (= हजार नेत्रों वाला) कब? कैसे? और क्यों? हुआ- इस स्वाभाविक जिज्ञासा की पूति के लिये रूपकवादियों के पास वया उत्तर विद्यमान है- यह भी तो एक कठिन समस्या है। इसलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने ज्योंही यौगिक सहस्राक्ष शब्द का कार्यकारण-पुरस्सर मनन आरम्भकिया त्योंही उन्हें उसमें इतिहास की झलक दीख पड़ी- जिसका निरूपण वेदव्यास जी ने पुराण ग्रन्थन के समय उपर्युक्त रीति से किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अहल्या के प्रसङ्ग में इन्द्र को गोतम जी ने सहस्र-भग हो जाने का शाप दिया, परन्तु पीछे प्रार्थना करने के बाद शापानुग्रह करते हुये सहस्र भगों के बजाय सहस्रनेत्र होने का आशीर्वाद दिया। पुराणों में इन्द्र के सहस्राक्ष होने के सम्बन्ध में जो यह विवेचना की है वह यौगिक सहस्राक्ष की समाधिगम्य कार्य कारण कल्पना ही समझनी चाहिये। इसलिये वेदोक्त सहस्राक्ष शब्द भी इस आख्यान की ऐतिहासिकता का प्रबल निदर्शक है। इस तरह वैदिक-स्वरूप के मूल शब्दों से ही जब इस आख्यान की ऐतिहासिकता भी सिद्ध है, फिर किसी भी वेदाभिमानी को गजनि-मीलिका न्याय से पौराणिक-स्वरूप पर आक्षेप करने का क्या अधिकार है? यदि वैदिक और पौराणिक, दोनों स्वरूपों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो एक सीमा तक मानव समाज में वैदिक-स्वरूप के कारण ही दुराचार की श्रभिवृद्धि की आशङ्का हो सकती है, क्योंकि वहां इन्द्र को स्पष्ट शब्दों में ग्रहल्या का जार कहते हुये भी उसके लिये हवि: प्रदान करने का उल्लेख किया है। **क्रमश: ...**

'मूर्ख दिवस'

योगेश कुमार गोयल

विश्वभर में 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला 'मूर्ख दिवस' केवल एक साधारण दिन नहीं बल्कि हंसी, उल्लास और हल्के-फुल्के मजाक का ऐसा अवसर है, जो लोगों को रोजमर्रा की तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ पल के लिए राहत प्रदान करता है। इस दिन छोटे-बड़े, बच्चे-बुजुर्ग, सभी एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और बिना किसी दुर्भावना के हंसी-ठिठोली के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इस दिवस की सबसे खास बात यह है कि इसमें किए जाने वाले मजाक आमतौर पर हानिरहित होते हैं। लोग ऐसी कल्पनात्मक या मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर सामने वाला आसानी से विश्वास कर ले और बाद में जब सच्चाई सामने आए तो दोनों पक्ष हंसी में डूब जाएं। कई बार तो बड़े-बड़े बुद्धिमान और चतुर लोग भी इस दिन मजाक का शिकार बन जाते हैं, जिससे वातावरण और भी मनोरंजक हो उठता है।

यह परंपरा केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रही है बल्कि बड़े मीडिया संस्थान, प्रतिष्ठित कंपनियां और नामी ब्रांड भी इस दिन अनोखे और रचनात्मक 'प्रैंक्स' के जरिए लोगों का मनोरंजन करते हैं। इतिहास में कई रोचक उदाहरण मिलते हैं। 1957 में बीबीसी ने 'स्पेगेटी ट्री' की खबर प्रसारित की, जिसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में पेड़ों पर स्पेगेटी उगती है। हजारों लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। इसी तरह 1996 में बर्गर किंग ने 'लेफ्ट-हैंड व्हॉपर' बर्गर की घोषणा कर लोगों को चौंका दिया। डिजिटल युग में यह परंपरा और भी व्यापक हो गई है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसे मजाक कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी लोग सच्ची खबरों को भी 'अप्रैल फूल' समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। मूर्ख दिवस की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं। एक प्रचलित धारणा के अनुसार, प्राचीन समय में कई देशों में नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता था। जब कैलेंडर प्रणाली में बदलाव हुआ और नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी, तब भी कुछ लोग पुरानी परंपरा का पालन करते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए 1 अप्रैल को 'मूर्ख दिवस' के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे-धीरे यह परंपरा मनोरंजन का माध्यम बन गई। भारतीय संस्कृति में भले ही यह परंपरा पश्चिम से आई हो लेकिन इसके मूल में निहित भावना (हंसी, आनंद और आपसी मेलजोल) भारतीय जीवन मूल्यों से भी मेल खाती है। आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवनशैली में जहां लोगों के पास हंसने का समय भी कम हो गया है, वहां यह दिन एक सुखद अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मजाक की सीमा शालीनता और संवेदनशीलता के भीतर ही होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अपमान करने या नुकसान पहुंचाने वाला मजाक इस दिवस की भावना के विपरीत है। मूर्ख दिवस का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर हंसना और खुशियां बांटना है।

नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा के बाद भी बहुत कुछ करना होगा

अशोक मधुप

काफी पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मार्च 2026 की अवधि से एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बड़ी घोषणा की। नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवाद अब लगभग समाप्त हो चुका है। आदिवासी इलाकों में असली न्याय पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि 2014 के बाद केंद्र सरकार की सख्त नीति, सुरक्षा अभियान और विकास योजनाओं के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार नकसल प्रभावित क्षेत्र में तेजी से विकास करा रही है। शिक्षा के लिए स्कूल और उपचार के लिए वहां अस्पताल खुल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की जड़ें खत्म हो रही हैं और आदिवासियों की आवाज अब संसद तक पहुंची है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने समस्या को बढ़ने दिया। मोदी सरकार के फैसलों से हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल विचारधारा आदिवासियों को गुमराह करती है और अब देश नक्सलवाद मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने नक्सलियों से बातचीत नहीं, बल्कि उन्हें खत्म कर विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जो हथियार उठाएगा, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि नक्सलियों का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पोलित ब्यूरो और कमेटी अब खत्म हो चुकी है। काफी मारे गए, बहुतों ने सरेंडर किया। कुछ अभी फरार हैं।

शाह ने कहा कि देश अब नक्सलमुक्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि कई बड़े ऑपरेशन जैसे बुढ़ा, थंडरस्टॉर्म और ब्लैक फॉरेस्ट चलाए गए। इनमें भारी मात्रा में हथियार, आईईडी फैक्ट्री और अनाज बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा के बड़े इलाके अब नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की भूमिका को उन्होंने अहम बताया।

केंद्रीय गृहमंत्री ने बताया कि आजादी के समय देश संसाधनों की कमी और विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था। कई दूर-दराज के इलाकों तक सरकार की पहुंच नहीं थी, सड़कों और सुविधाओं का अभाव था। ऐसे हालात में कुछ संगठनों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। जहां राज्य की पकड़ कम थी, उन्हीं इलाकों को रेड कॉरिडोर बनाया गया। भोले-भाले आदिवासियों को भेदभाव और शोषण के नाम पर भड़काया गया और उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए। हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध भेदभाव नहीं, बल्कि विकास की कमी थी, जिसका इस्तेमाल कर हिंसा को बढ़ावा दिया गया।

शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑल एजेंसी अप्रोच अपनाई। इसमें सीएपीएफ, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। फंडिंग और स्पोर्ट सिस्टम पर प्रहार किया गया। सरेंडर नीति लागू की गई। इसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक मदद और पुनर्वास दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव तक अपनी पहुंच बनाई, इससे नक्सलवाद कमजोर हुआ।

उन्होंने दावा किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। हजारों किलोमीटर सड़कें बनीं, मोबाइल टावर लगाए गए, बैंक, एटीएम और डाकघर खोले गए। शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल, आईटीआई और कौशल केंद्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि विकास ही नक्सलवाद खत्म करने का सबसे बड़ा कारण बना।

शाह ने कहा कि नक्सलवाद गरीबी से नहीं, बल्कि विचारधारा से पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और बंदूक के जरिए सत्ता चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों को बरगलाकर उनके हाथ में हथियार दिए गए और विकास को रोका गया।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आगे भी सख्ती और विकास दोनों पर काम जारी रखेगी। उन्होंने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब देश बंदूक से नहीं, संविधान से चलेगा और यही असली जीत है। गृह मंत्री के अनुसार, जिस रेड कॉरिडोर का विस्तार कभी पशुपति से तिरुपति तक माना जाता था, वह अब सिमटकर केवल कुछ जिलों तक रह गया है। 2014 में जहाँ 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2025-26 तक यह संख्या घटकर मात्र एक अंक में रह गई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग, जो कभी नक्सलियों का अभेद्य किला माना जाता था। अब वह सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है और वहां विकास की किरणें पहुँच रही हैं।

सरकार के इन दावों की पुष्टि जमीनी आंकड़ों से भी होती है। पिछले कुछ वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। सुरक्षा बलों की शहादत के आंकड़ों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऑपरेशन कगार और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे लक्षित अभियानों के माध्यम से सुरक्षा बलों ने नक्सली नेतृत्व की कमर तोड़ दी है। 2025 के दौरान ही 300 से अधिक नक्सली मारे गए। इनमें कई शीर्ष कमांडर शामिल थे। इसके साथ ही, हजारों की संख्या में कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है,। यह समर्पण इस बात का प्रतीक है कि अब इस विचारधारा का आकर्षण खत्म हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद, इन सफलताओं के बावजूद नक्सलवाद की चुनौतियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती भौगोलिक विषमता है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जैसे घने वन क्षेत्र आज भी सुरक्षा बलों के लिए कठिन परीक्षा बने हुए हैं। नक्सलियों ने अपने पैर पीछे जरूर खींचे हैं, लेकिन वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। वे अक्सर घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का लाभ उठाकर छापामार हमले करने की ताक में रहते हैं। इसके अलावा, अर्बन नक्सलिज्म या वैचारिक उग्रवाद एक नई चुनौती बनकर उभरा है। शहरों में बैठे कुछ बौद्धिक समूह नक्सलियों को वैचारिक और रसद सहायता प्रदान करते हैं। इससे इस समस्या की जड़ें गहरी बनी रहती हैं। जब तक इन वैचारिक और वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक उग्रवाद के पुनर्जीवित होने का खतरा बना रहेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती स्थानीय आदिवासियों के बीच विश्वास की बहाली है। दशकों से विकास की मुख्यधारा से कटे होने के कारण, कई क्षेत्रों में ग्रामीण अब भी सुरक्षा बलों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नक्सली अक्सर इस अविश्वास का फायदा उठाते हैं और ग्रामीणों को ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय जनता के बीच के इस गवर्नेंस वैक्यूम को भरना एक लंबी प्रक्रिया है। केवल सड़कों या मोबाइल टावरों का निर्माण पर्याप्त नहीं है; लोगों को यह महसूस कराना होगा कि सरकार उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षक है। इसके साथ ही, पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय की कमी भी कई बार बाधा बनती है, क्योंकि नक्सली एक राज्य में दबाव बढ़ने पर दूसरे राज्य की सीमा में शरण ले लेते हैं। विकास के मोर्चे पर, सरकार को नियत नेल्लानार (आपका अच्छा गांव) जैसी योजनाओं को और विस्तार देना चाहिए, जो अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर केंद्रित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावी हथियार है। जब आदिवासियों के बच्चों के पास स्कूल होंगे और उनके युवाओं के पास रोजगार के अवसर होंगे, तो नक्सलियों की भर्ती प्रक्रिया स्वत: ही बंद हो जाएगी।

आज का इतिहास

1863 अमेरिका में पहली बार युद्धकाल का भर्ती कानून प्रभाव में चलाया गया।
1865 पाँच कांटे रखने का आदेश दिया, कन्फेडरेट जनरल जॉर्ज पिकेटिंस्टेड ने लगभग 3,000 खो दिए।
1867 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में खोली गयी।
1868 हैम्पटन सामान्य और कृषि संस्थान हैम्प्टन के वर्जीनिया में स्थापित किया गया।
1886 अमेरिका में कामगारों के लिये समय निर्धारित करने के लिए हड़ताल की गई, जिसके उपरांत 01 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस घोषित किया गया।
1893 संयुक्त राज्य अमेरिका में नौसेना चीफ पैटी ऑफिसर के पद पर स्थापित किया गया।
1918 ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने कर्मियों को उड़ान भरने की शक्ति देना शुरू कर दिया।
1946 सिंगापुर एक क्राउन कॉलोनी बना।
1949 टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई।
1956 अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणुशास्त्री जोनास सॉल्क द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन जनता के लिए उपलब्ध करायी गयी।
1958 बीबीसी रेडियोफ़ोनिक कार्यशाला की स्थापना की।
1970 आयातित मशीनों को कुचलने के लिए पहले 670,000 से अधिक गार्मलिन उत्तरी अमेरिका में जारी किए गए थे।
1976 ऐप्पल कंप्यूटर कंपनी स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज्नियाक द्वारा बनाई गई।
1978 फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि फिलीपीनकॉलेज ऑफ कॉमर्स एक पिल्ला बन जाए।
1996 बैंक ऑफ़ टोकियो और मित्सुबिशी बैंक के विलय से बना विश्व का सबसे बड़ा बैंक न्यू बैंक आफ़ टोकियो-मित्सुबिशी ने अपना कार्य आरम्भ किया।
1996 केंटकी ने 58 वें एनसीएए पुरुषों की बेसबॉल चैम्पियनशिप में सिरैक्यूज़ को 76-67 से हराया।
1996 नोवा स्कोटिया में हैलिफ़ैक्स शहर को क्षेत्रीय नगरपालिका बनाया गया।
1997 स्विटजरलैंड की मार्टिना हिंगिस टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र की नंबर एक महिला खिलाड़ी बनीं।
1997 गोर्डी होवे ने 65 साल की उम्र में सिरैक्यूज़ क्रंच के साथ एएचएल गेम खेलना शुरू किया।
1998 मिनेसोटा में वर्ल्ड आइस पेरिस फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी।

संवैधानिक संस्थाओं पर उठते सवालों से कमजोर होता लोकतंत्र

योगेंद्र योगी

देश में समय के साथ लोकतंत्र के परिपक्व होने के बजाए कमजोर होने की आहट आ रही है। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर—तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के इस घेरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं।

लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था। कई बार मुझे बोलने से रोका गया है। पहली बार लोकसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है।

नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी। नेशनल एवरेज 66% था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी। नेशनल एवरेज 80% था। 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी, जबकि नेशनल एवरेज 76% था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए।

लोकसभा स्पीकर बिरला के कामकाज के तौर—तरीकों पर उनको हटाने का प्रस्ताव लाकर नाराजगी जताने से पहले राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ पर इसी तरह के

आरोप लगाते हुए विपक्ष ने दिसंबर 2024 में उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया था। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आरोप लगाया था कि कि धनखड़ एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अक्सर अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें सदन में बोलने से रोकते हैं। खरगे ने यह भी दावा किया था कि सदन में हुई गड़बड़ी के लिए स्वयं श्री धनखड़ जिम्मेदार हैं।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष का सभापति धनखड़ को हटाने का नोटिस खारिज कर दिया था, जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। हरिवंश ने यह कहते हुए विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया कि यह तथ्यों से परे है और इसका मकसद केवल प्रचार हासिल करना है। उपसभापति ने कहा था कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है। राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है।

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया गठबंधन) के घटक दलों ने सभापति धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 दिसंबर को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा था। नोटिस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके नेता तिरुचि शिवा और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, मुख्य सचेतक जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला तथा कई अन्य सीनियर सदस्यों ने धनखड़ के खिलाफ दिए गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।

संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों के खिलाफ हटाने के प्रयासों के अलावा विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में सौंपा है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को हटाने के विपक्ष के प्रयास सफल नहीं हो सके, उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के भी पारित होने की संभावना क्षीण है। विपक्ष के पास महाभियोग पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। इस तरह के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को हटाने के लिए एकजुट विपक्ष के प्रयास बेशक सफल नहीं हो पाएं, किन्तु ऐसे प्रयासों से इन पदों की गरिमा कम हुई है। देश में विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करके मजबूत लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता।

संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवालों के घेरे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) का पद भी आ चुका है। इस पद के चयन के लिए कमेटी बनाने की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका लंबित है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की याचिका में कहा गया है कि अभी कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इस पद की अहमियत को देखते हुए इसके लिए योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति का चयन जरूरी है इसलिए, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए कैग के चयन का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है।

संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर उठते सवाल भारतीय लोकतंत्र में एक गंभीर विषय बन गए हैं। इन संस्थाओं को परिपक्वता से काम करना चाहिए ताकि उन पर सवाल न उठें। विपक्ष का आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि वे संविधान के अनुसार काम कर रही हैं। यह बहस लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

हूती विद्रोहियों के दखल से खुला नया मोर्चा

पवन

पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में शनिवार को हूती विद्रोहियों के दखल से जहां इस युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया है, वहीं बाजारों में पहले से ही चल रही उथल-पुथल के और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी पैदा हो गई है। गौरतलब है कि इस्लामी विद्रोही गुट हूती ने इस्राइल के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद यह चेतावनी भी जारी की, कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक ईरान के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती।

वर्ष 2014 से ही हूती उत्तर-पश्चिमी यमन पर कब्जा जमाए हुए है, जिसके चलते होर्मुज मार्ग से इतर एक अन्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग लाल सागर पर इसका नियंत्रण है। गौरतलब है कि फलस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए गाजा संघर्ष के दौरान लाल सागर और अदन की खाड़ी से होते हुए स्वेज नहर की ओर जाने वाले मालवाहक जहाजों पर हूती ने लगातार हमला किया था। शनिवार से पहले, जब हूती विद्रोही इस ताजा संघर्ष से दूर थे, तो होर्मुज मार्ग बंद होने के कारण लाल सागर का महत्व और भी बढ़ गया था।

सऊदी अरब ने अपने तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर के यानबू बंदरगाह की ओर मोड़ दिया था, ताकि वह होर्मुज मार्ग से बच सके। लेकिन, अब जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को शत्रु देशों के लिए बंद कर दिया है, तो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के फिर से लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हूतियों द्वारा ये हमले तब किए गए हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच परोक्ष रूप से वार्ता शुरू होने की खबरें हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि कुछ ही हफ्तों में युद्ध खत्म हो सकता है। खुद ट्रंप ने भी यह संकेत दिया है कि ईरान में उनके प्रशासन ने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, और इशारा किया है कि युद्ध तय समय-सीमा के भीतर समाप्त हो सकता है। ऐसे में, इस संघर्ष में हूती के शामिल होने से शांति वार्ता की उम्मीद धूमिल लग रही है। सबसे अहम बात यह है कि अगर युद्ध खत्म भी हो गया, तो इस युद्ध का असर लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और युद्ध के विनाश का असर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।

जैसे-जैसे अमेरिका मध्यावधि चुनावों की तरफ बढ़ रहा है, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर नो किंग्स प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रंप और उनकी पार्टी की चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं। पश्चिम एशिया का संकट जिस ओर बढ़ रहा है, उससे दुनिया एक दीर्घकालिक युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। अगर वक्त रहते इस आग को नहीं बुझाया गया, तो इसके दुष्परिणाम न केवल पश्चिम एशिया, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।

खाड़ी देशों के युद्ध के परिणाम और भारत की स्थिति

मंगत राम पासला

खाड़ी देशों के युद्ध के भयानक परिणाम न केवल संबंधित क्षेत्र के लोगों को, बल्कि दुनिया के सभी देशों के लोगों को भुगतने होंगे। यह प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू भी हो चुकी है। अमरीका-इसराईल ने बिना किसी उकसावे या उचित कारण के ईरान पर हमला बोल दिया। युद्ध छेडने का बहाना बेशक ईरान के पास मौजूद परमाणु हथियारों के भंडारों से अमरीका-इसराईल को संभावित खतरे का बनाया गया है, पर अब न केवल दुनिया भर के लोगों, बल्कि अमरीका के भीतर राष्ट्रपति के करीबी मित्रों ने भी यह बात खुलेआम स्वीकार कर ली है कि ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यह युद्ध अपने चहेते इसराईली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उत्तेजना भरी सलाहों से शुरू किया है।

अमरीकी राष्ट्रपति की तमाम धमकियों के बावजूद 'नाटो' के सांझेदार देशों ने अमरीका का साथ देने और इस युद्ध में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है। इससे भी आगे, कमाल की बात यह पता चली है कि ट्रम्प ने यह युद्ध अमरीकी संसद से आवश्यक मंजूरी लेने की बजाय, अपने दामाद, बेटी, बेटे और एक मित्र की सलाह पर छेड़ा है। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले देश अमरीका की कमान ट्रम्प जैसे मूर्ख के हाथ में हो, तो दुनिया के लोग शांति से मिल-जुल कर रहने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इस युद्ध से दुनिया भर के देशों की बहुसंख्यक आबादी को खाद्य वस्तुओं की भारी कमी, तेल-गैस और इससे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि, महंगाई और बेरोजगारी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध के कारण हजारों बेगुनाहों की मौतें (इनमें ईरान के स्कूल में पढने वाली सैंकड़ों छोटी बच्चियां भी शामिल हैं), मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों की भारी

तबाही और पर्यावरण में फैल रहा जहर पूरी मानवता के लिए जी का जंजाल बनेगा। इस युद्ध ने दुनिया के सारे कायदे-कानून ताक पर रखकर किसी भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र (जैसे इराक और वेनेजुएला) पर हमला करके कब्जा करने की अमरीका की लालसा को भी उजागर किया है।

इस युद्ध ने भारत की मोदी सरकार द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ की गई रणनीतिक सांझेदारियों के परिणामस्वरूप अपनाई गई वर्तमान विदेश नीति का दुनिया भर में दीवाला निकाल दिया है। भारत ने 2 सैन्य गुटों ('नाटो' और 'वारसा') से अलग रहकर गुटनिरपेक्ष देशों का सांझा मंच खड़ा करने में बहुमूल्य योगदान दिया था। परंतु अब भारत ने डटकर ईरान के साथ खड़े होने की बजाय अमरीका-इसराईल युद्धबाज गुट का पक्ष लिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले समय में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों का ऐसा मजाक उड़ाया, जिसे कोई भी स्वाभिमानी स्वतंत्र देश कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे दुनिया भर में भारतीय राजनेताओं की नपुंसक राजनीति भी बेपर्दा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प के इन अपमानजनक बयानों के खिलाफ अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं बोला। भारत के निमंत्रण पर नौसेना के अभ्यास में हिस्सा लेने आए ईरान के समुद्री जहाज में सवार 97 सैनिकों को अमरीकी सेनाओं द्वारा हमला करके तब मार दिया गया, जब वे अपने देश ईरान वापस लौट रहे थे। अमरीका की इस अत्यंत निंदनीय कार्रवाई की निंदा करना तो दूर, भारत द्वारा सैनिकों की मौत पर शोक का औपचारिक प्रकटीकरण तक नहीं किया गया।

अमरीका के साथ मोदी सरकार की दोस्ती का 'परिणाम' भारत-अमरीका के बीच होने वाले 'मुक्त व्यापार समझौते' में भारत के लिए कई प्रतिकूल शर्तें स्वीकार किए जाने के भयानक नतीजे भारत के किसानों, छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों और व्यापारियों की तबाही के रूप में सामने आने वाले हैं। स्पष्ट है कि अमरीका अपने किसानों को भारी सबसिडी देकर तैयार की गई कृषि वस्तुएं जैसे मक्का, सोयाबीन का तेल, फल, सूखे मेवे आदि भारतीय बाजार में उतारकर हमारी किसानी को खेती से बाहर कर देने की तैयारियां किए बैठा है। हमारा देश साम्राज्यवादी गुलामी के 'नव-उपनिवेशवादी' दौर में पहुंचने जा रहा है, जहां सरकार तो भारतीय लोगों की ही होगी, परंतु आर्थिक नीतियां, व्यापारिक और राजनीतिक फैसले अमरीका की मंजूरी से ही लिए जाएंगे। इसकी ताजा मिसाल खाड़ी युद्ध के दौरान ऊर्जा की कमी के मद्देनजर अमरीका द्वारा बड़े अहंकारी ढंग से भारत को सिर्फ 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दिए जाने से मिलती है। ड्क्षचता इस बात की है कि भारत को साम्राज्यवादी देश अमरीका और इसके सांझेदारों द्वारा बनाए गए आर्थिक और राजनीतिक 'चक्रव्यूह' से बाहर निकलने के लिए हमें आजादी की एक और जंग लडनी पड़ सकती है। यह जंग 1947 में प्राप्त की गई आजादी के लिए लड़े गए लंबे राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की तुलना में कहीं अधिक कठिन और खतरनाक होगी।

नेपाल की नयी सरकार से उम्मीदें बहुत हैं

संजीव राय

बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गये हैं। विगत आठ सितंबर से पहले उन्हें नेपाल से बाहर कम लोग जानते थे। वर्ष 2012 में अपने पहले म्यूजिक एलबम से चर्चा में आये बालेंद्र शाह ने दस साल में अपनी छवि राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आक्रोश को स्वर देने वाले रैप गायक की बनायी। उनके तेवर नेपाली स्वाभिमान जगाने वाले थे, जिसमें नेपाल को अंतरराष्ट्रीय दबाव से मुक्त कर एक सशक्त देश बनाने की आकांक्षा शामिल थी। यह सब तब हो रहा था, जब नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के लंबे संघर्ष के बाद नेपाल से 2008 में राजशाही विदा हो चुकी थी। आम जनता को उम्मीद थी कि 2015 के नये संविधान और प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव के रास्ते मुख्यधारा के राजनीतिक दल एक समृद्ध नेपाल बनाने के सपने को जमीन पर उतारने में सफल होंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।

वर्ष 2017 से 2025 के बीच गठबंधन सरकारों में सत्ता की अदला-बदली का खेल शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के बीच चलता रहा। ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री 2025 तक सत्तर की उम्र पार कर चुके थे और सत्ता के लोभ में इनके दलों की विचारधारा और सिद्धांत पीछे छूट रहे थे। अस्थायी सरकारों के उस दौर में नेपाल में बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक असमानता बढ़ती गयी। नेताओं पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के गहरे आरोप लगे। इसी बीच 2022 में बालेंद्र शाह ने जब युवाओं का आह्वान करते हुए, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मुख्य राजनीतिक दलों को दरकिनार कर काठमांडू में मेयर का चुनाव जीता और राजधानी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये, तो उनका राजनीतिक कद बढ़ गया। उन्होंने खुद को पुरानी पीढ़ी के राजनेताओं के विकल्प के रूप में पेश किया।

वर्ष 2022 में ही लोकप्रिय टीवी एंकर रवि लामिछाने ने कुछ उच्च शिक्षित युवाओं के साथ आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की और राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरे। देश के युवा सोशल मीडिया पर भ्रष्ट राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। युवाओं के बढ़ते आक्रोश को रोकने के लिए सितंबर, 2025 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली ने सोशल

मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, तो क्षुब्ध युवा सड़क पर उतर गये, सरकार को घुटने टेकने पड़े, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश को आम चुनाव में जाना पड़ा। सोशल मीडिया ने ही बालेंद्र शाह और सौदान गुरुंग जैसे युवाओं को सत्ता तक पहुंचाया है। इस महीने हुए चुनाव में बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद तक भी सोशल मीडिया ने ही पहुंचाया है।

बालेंद्र शाह को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के पीछे युवाओं के लिए रोजगार सृजन, देश की आर्थिक उन्नति और भ्रष्टाचार के खात्मे जैसे वादों की लंबी सूची है। चुनाव में आरएसपी की जीत और नेपाल की पारंपरिक पार्टियों की हार के बीच 'माध्यम', 'सोच' और 'नेतृत्वकर्ता' का फर्क साफ है। पर सरकार की आलोचना करने और सरकार चलाने में फर्क होता है। चुनाव में दो तिहाई बहुमत हासिल करने वाली नयी सरकार से उम्मीदें बहुत हैं और नेताओं पर अपने किये गये वादे पूरा करने का दबाव भी है। लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, तो असंख्य लोग आर्थिक अवसर पाते ही देश में लौटना चाहते हैं। पर युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच क्या नेपाल आर्थिक उन्नति का कोई नया मॉडल दिखा सकता है?

आर्थिक समृद्धि के लिए दूसरे देशों के साथ नेपाल के रिश्तों और व्यापार की शर्तों की अहम भूमिका होगी। अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते बालेंद्र शाह की सरकार को अतिरिक्त संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है और नेपाल की जीडीपी में खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस की हिस्सेदारी करीब तीस फीसदी है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर उभार के साथ यह भी संभव है कि बालेंद्र शाह पड़ोसी देशों के साथ कुछ मुद्दों पर अब अलग स्टैंड लें। नेपाल के साथ ऐतिहासिक संबंधों के चलते भारत सरकार काठमांडू के साथ सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने पर बालेंद्र शाह को न सिर्फ बधाई दी है, बल्कि दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद भी जताई है। भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा के साथ नेपाल में एक मजबूत सरकार बनने से सीमा के आर-पार अपराध, तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी। भारत और नेपाल बिजली उत्पादन, कृषि ,शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं।

अपने शपथ ग्रहण समारोह में बालेंद्र शाह ने जिस तरह हिंदू और बौद्ध परंपरा के मंत्रोचार और शंखनाद को शामिल किया है, उससे स्पष्ट है कि वह नेपाल की मध्यमार्गी राजनीति के साथ अपना विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह की भूमिका और पड़ोसी देशों के साथ उनकी सरकार के रिश्तों का मूल्यांकन तो आने वाला समय बतायेगा, लेकिन घरेलू राजनीति भी उनके लिए चुनौतियों से भरी है। आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने के साथ तालमेल बिठाने के साथ उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने का दबाव भी उन पर होगा। जेन जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट पर नयी सरकार क्या कार्रवाई करती है, यह देखना होगा, लेकिन सरकार गठन के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी से नयी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं और विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसे बदले की भावना से की गयी कार्रवाई बता रही हैं। ऐसे में, सरकार के खिलाफ संसद से सड़क तक राजनीतिक आंदोलन होने की आशंका भी बढ़ गयी है।

ऐसे में, सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं को धैर्य के साथ देखना होगा कि पार्टी और सरकार के बीच तालमेल कैसे बैठता है तथा पार्टी कैसे एकजुट रहती है। नेपाल के सभी इलाकों के लोगों को सेना, पुलिस और अन्य रोजगार क्षेत्रों में समान अवसर मिले, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा। नेपाल के मीडिया को इस नये प्रयोग को उम्मीद से देखना होगा कि अगले बारह महीने तक इस सरकार का रुझान क्या रहता है। आने वाला समय बतायेगा कि क्या वास्तव में नेपाल में बिना भ्र्ष्टाचार के विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है अथवा राजनीति की नयी पिच और प्रयोग भी कुछ नये अभिजनों के उभार तक सीमित रहते हैं?

कूटनीति के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिकी स्वाभिमान

दिलीप कुमार पाठक

दुनिया के नक्शे पर जब भी युद्ध की आहट होती है, तो सबसे पहले व्हाइट हाउस की हलचलें तेज हो जाती हैं। लेकिन ये युद्ध अमेरिका के कुछ अलग है, और महंगा भी पड़ रहा है, एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी मिसाइलें ईरान के आसमान को चीर रही हैं, तो दूसरी तरफ पेंसिलवेनिया और ओहायो के गैस स्टेशनों पर खड़ा एक आम अमेरिकी नागरिक अपनी खाली होती जेब देख रहा है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि वाशिंगटन की सैन्य ताकत जितनी बढ़ रही है, वहां के आम आदमी का भरोसा अपनी सरकार और अपनी अर्थव्यवस्था पर उतना ही कम होता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट का नारा तो दिया था, लेकिन आज का मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे युद्ध की जिद ने उस वादे को ही हाशिए पर धकेल दिया है।

राजनीतिक गलियारों में आज ट्रंप की स्थिति किसी मज़ाक से कम नहीं रह गई है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि वे अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज वे खुद एक नए और भीषण युद्ध के नायक बने बैठे हैं। इसे नियति का क्रूर मजाक ही कहेंगे कि जिस शांति का वादा उन्होंने किया था, उसे उन्होंने मिसाइलों के धुएं में उड़ा दिया है। वैश्विक मंच पर ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही है जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। नाटो देशों को फंडिंग रोकने की धमकी देना और फिर उन्हीं से युद्ध में सहयोग मांगना, उनकी कूटनीतिक अपरिपक्वता को जगजाहिर कर रहा है। आज दुनिया के कई देशों में ट्रंप के विरोधाभासी बयानों पर चर्चा हो रही है और कूटनीति के जानकार इसे हड़बड़ी में लिया गया आत्मघाती कदम बता रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि ट्रंप जिस सुपरपावर होने का दंभ भर रहे हैं, उसकी बुनियाद घर के भीतर ही दरक रही है। जब राष्ट्रपति टीवी पर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता गिनाते हैं, तब मिडिल क्लास अमेरिकी अपने बच्चों की स्कूल फीस और घर के किरायों के जुगाड़ में माथापच्ची कर रहा होता है। यह कैसा राष्ट्रवाद है जो अपने ही लोगों को महंगाई की आग में झोंककर विदेशी धरती पर अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है? लोग अब दबी जुबान में पूछने लगे हैं कि क्या एक बिजनेसमैन राष्ट्रपति को इतना भी मुनाफा-नुकसान समझ नहीं आता कि जंग की कीमत हमेशा आम लोगों की थाली से वसूली जाती है? ट्रंप का अहंकार आज उन्हें उस मोड़ पर ले आया है जहां उनके अपने समर्थक भी अब उनके फैसलों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कूटनीति की मेज पर बैठे बड़े खिलाड़ी उनके इस व्यवहार को गंभीरता से लेने के बजाय एक अस्थिर नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां एक महान देश का मुखिया दुनिया के सामने उपहास का पात्र बन जाता है।

आंकड़ों की बात करें तो स्थिति और भी भयावह है। युद्ध की आहट मात्र से अमेरिका में महंगाई दर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। शेयर बाजार में हर रोज अरबों डॉलर स्वाहा हो रहे हैं। एक आम अमेरिकी परिवार, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा था, अब बढ़ती तेल की कीमतों और महंगे राशन से बेहाल है। वहां के आधे से ज्यादा नागरिक अब यह मानने लगे हैं कि सरकार को अपनी सेना की ताकत दिखाने से ज्यादा अपनी जनता की फिक्र करनी चाहिए। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया को तबाह करने वाली सबसे आधुनिक मिसाइलें तो हैं, लेकिन अपने नागरिकों को सस्ता ईंधन और मानसिक शांति देने का कोई ठोस रास्ता नहीं है।

मानवीय नजरिए से देखें तो यह सिर्फ डॉलर और सेंट का मामला नहीं है। यह उस अमेरिकी सपने के टूटने की कहानी है, जिसे दिखाकर वोट मांगे गए थे। युद्ध के मोर्चे पर डटे सैनिकों के परिवार आज डरे हुए हैं, वहीं मध्यम वर्ग के लिए मंदी शब्द अब सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उनके घर की दहलीज पर खड़ी हकीकत बन चुका है। ट्रंप की नीतियां आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हैं, जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता या तो और बड़े युद्ध की ओर जाता है या फिर आर्थिक तबाही की ओर। कूटनीति की बिसात पर मोहरे तो हिल रहे हैं, लेकिन जीत का अहसास कहीं गायब है।

अंत में, यह समझना जरूरी है कि कोई भी राष्ट्र केवल अपनी सैन्य शक्ति से महान नहीं बनता। असली महानता तब आती है जब उस राष्ट्र का नागरिक खुद को सुरक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न महसूस करे। आज अमेरिका सैन्य रूप से भले ही सबसे ताकतवर दिख रहा हो, लेकिन एक आम नागरिक की कमजोर जेब उस खोखली ताकत की पोल खोल रही है। ट्रंप का यह युद्ध प्रेम उन्हें इतिहास में एक रक्षक के तौर पर दर्ज कराएगा या एक ऐसे शासक के रूप में जो अपने ही फैसलों में उलझ गया, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल, वाशिंगटन के गलियारों में जो चर्चा है, वह दरअसल उस बेचैनी की है जो बता रही है कि कैसे एक गलत सौदे ने देश के भविष्य को दांव पर लगा दिया है।

सोशल मीडिया के दबाव में मत आइए, खुद को अपनाइए : कुब्रा सैत

एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दिखने वाले परफेक्ट बॉडी स्टैंडर्ड्स पर अपनी बात रखते हुए बताया है कि किस तरह से सोशल मिडीया का दखल व्यक्तिगत जीवन में बढ़ गया है। साथ ही इस पर कुब्रा ने लोगों को सलाह भी दी है कि इन चीजों के लिए सोशल मीडिया को दोष देने के बजाय खुद के अंदर झांकना चाहिए। इस विषय में कुब्रा कहती हैं, असली समस्या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी असुरक्षाएं हैं। अगर इंसान का आत्मविश्वास मजबूत हो, तो बाहर की चीजें उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्होंने अपनी बात करते बताया कि वे खुद को फिट रखने पर ध्यान देती हैं, लेकिन किसी तरह के बदलाव का सहारा नहीं लेतीं। हालांकि, वह यह भी मानती हैं कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और ऐसे में हर किसी को चाहिए कि वे दूसरों को जज न करें।

कुब्रा कहती हैं, हर किसी की अपनी जर्नी होती है, अपनी पसंद होती है, इसलिए दूसरों को जज करने या उनसे खुद की तुलना करने की बजाय अपनी लाइफ और अपने सफर पर ध्यान दें। इन सबके अलावा अपने करियर के बारे में बात करते हुए कुब्रा ने यह भी बताया कि मेहनत और अनुशासन उनके लिए बहुत जरूरी रहे हैं।

हालांकि मुंबई आना उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिससे उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला। फिलहाल अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी कुब्रा कहती हैं कि उन्हें अपने काम से उम्मीद से ज्यादा मिला है और इसके लिए वह बेहद शुक्रगुजार हैं।

दूसरी बार मां बनीं सोनम कपूर बेबी बॉय को दिया जन्म

एक्ट्रेस सोनम कपूर के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनी हैं, उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। इसकी जानकारी सोनम ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है। सोनम अब दो बच्चों की मां बन गई हैं। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद शुक्रगुजार और प्यार से भरे दिलों के साथ, हमें 29 मार्च 2026 को अपने बेटे के आने की खुशखबरी सुनाते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारा परिवार और बड़ा हो गया है और उसके आने से हमारे दिल खुशियों से और भी ज्यादा भर गया है। 'रांझणा' फेम अभिनेत्री ने बताया कि उनका बड़ा बेटा वायु अब छोटे भाई को पाकर बहुत खुश है। सोनम ने आगे लिखा, वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत उत्साहित और खुश है और हम इस अनमोल नई जिंदगी के लिए खुद को बहुत धन्य महसूस करते हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और प्यार से भर दिया है।

पोस्ट के अंत में सोनम और आनंद ने लिखा, हम चार लोगों के परिवार के रूप में इस खूबसूरत नए सफर की शुरुआत करने के लिए शुक्रगुजार हैं। इस खुशखबरी को लेकर सोनम के परिवार और दोस्तों की ओर से ढेरों शुभकामनाएं मिलीं। करीना कपूर ने लिखा, बधाई हो सोना और आनंद। सोनम की बहन रिया कपूर ने दिल वाले इमोजी के साथ खुशी जताई। सोनम के चाचा संजय कपूर ने भी रेड हार्ट इमोजी के साथ अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा, दीया मिर्जा और हुमा कुरैशी ने भी कमेंट सेक्शन में बधाई दी।

सोनम कपूर ने पिछले साल नवंबर में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी जिसमें वह हॉट पिंक रंग का शानदार सूट पहने नज आई थीं। कैप्शन में सिर्फ एक शब्द लिखा था – मां।

सोनम कपूर ने मई 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूज से शादी की थी। दोनों कई सालों से रिश्ते में थे। सोनम ने अगस्त 2022 में अपने पहले बेटे वायु को जन्म दिया था।

धुरंधर की सफलता के बाद अब बादशाह की सवारी करेंगी सौम्या टंडन, शुरू की घुड़सवारी की ट्रेनिंग

अभिनेत्री सौम्या टंडन इन दिनों स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर सुर्खियों में छाई हैं। इस बीच, अभिनेत्री ने अपने नए शौक का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें घुड़सवारी का काफी शौक था, जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। फिल्म की सफलता के बाद सौम्या अब अपनी नई रुचि पर फोकस कर रही हैं। घुड़सवारी उनके लिए न सिर्फ नया शौक है बल्कि एक सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम भी है।

सौम्या ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इसमें वे घोड़ों के साथ नजर आ रही हैं। वहीं, कुछ तस्वीरों में वे घुड़सवारी सीखते हुए भी दिख रही हैं।

सौम्या ने लिखा, पहला दिन और पहली घुड़सवारी की क्लास।

अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें बचपन से ही घोड़े बहुत पसंद रहे हैं। उन्होंने लिखा, घोड़े बहुत सुंदर और नाजुक जानवर होते हैं। मैं हमेशा उनसे आकर्षित रही हूं। मैं बचपन में एक बड़े फार्म का सपना देखती थी, जहां खूबसूरत घोड़े और कुत्ते हों। मैं खुद उन घोड़ों पर सवारी करते हुए खुद को देखती थी।

सौम्या ने लिखा, पहला दिन थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मैंने घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया है, तो पहला दिन काफी खतरनाक और थकाऊ था। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन इस क्लास में मुझे एक नया दोस्त मिल गया। वह दोस्त है एक सुंदर सफेद घोड़ा, जिसका नाम 'बादशाह' है।

सौम्या ने मजाकिया अंदाज में बताते हुए लिखा, मैंने बादशाह से बहुत बातें कीं। सच कहूं तो वह बहुत अच्छा सुनने वाला था या शायद उसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनीं। मुझे लगता है कि हमारे बीच एक खास कनेक्शन बन गया है। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं।

अंत में सौम्या ने लिखा, फिर मिलेंगे बादशाह, जल्दी ही। उम्मीद है एक दिन हम साथ में घोड़ी चलाएंगे और तेज दौड़ लगाएंगे।

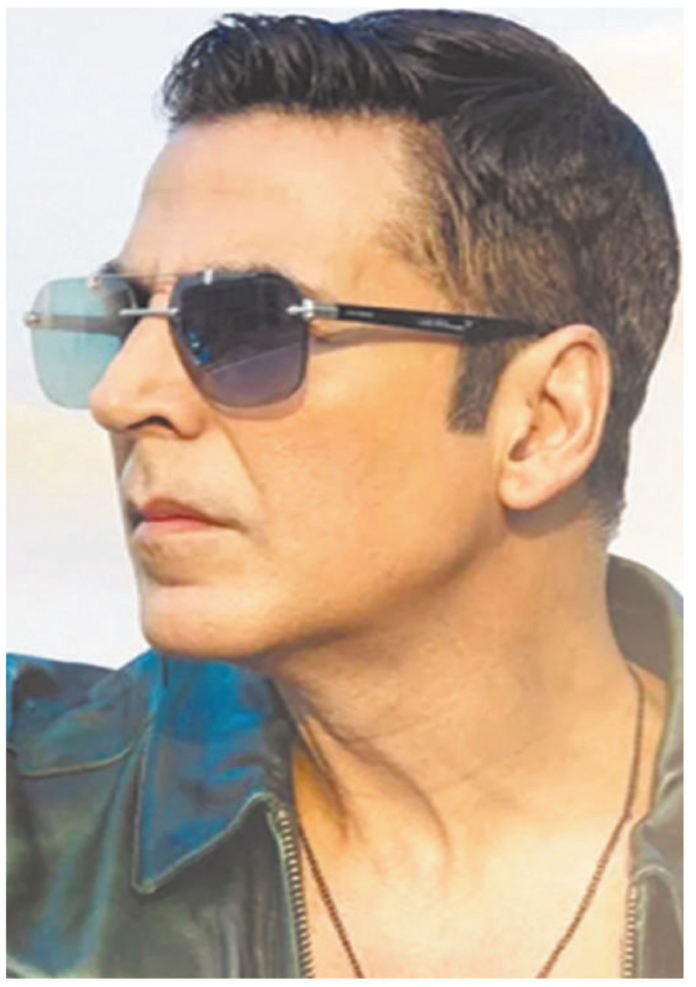

ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहलायीं मीना कुमारी? पर्दे से लेकर असल जिंदगी तक दर्द से भरी रही कहानी

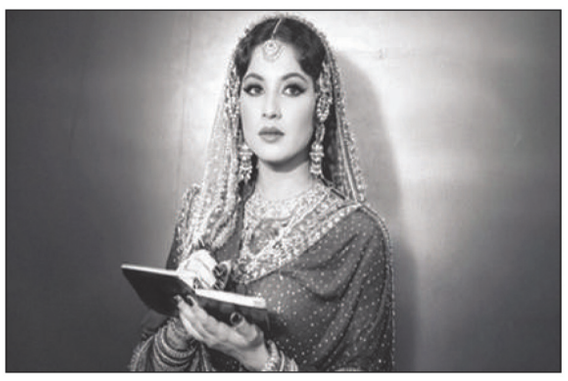

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को लोग आज भी याद करते हैं। उन्हें इंडस्ट्री में 'ट्रेजेडी क्वीन' कहा जाता था, और यह टैग उन्हें यूं ही नहीं मिला था। उनकी अदाकारी में जो दर्द नजर आता था, वह उनकी असल ज़िन्दगी का आईना था। उनका निधन 31 मार्च 1972 को हुआ। मीना ने महज 39 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनकी कहानी एक ऐसी कलाकार की कहानी है, जिसने पर्दे पर जितना दुख जिया, असल ज़िन्दगी में उससे कहीं ज्यादा सहा। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ। उनका असली नाम महजबीं बानो था। कहा जाता है कि मीना के पैदा होने से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे; उन्हें बेटे की चाह थी। बेटी के पैदा होने से वह इस कदर निराश हुए कि मीना को कुछ समय के लिए अनाथालय में छोड़ आए थे। हालांकि, बाद में मन बदलने पर उन्हें वापस घर भी ले आए थे।

घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मीना कुमारी को बहुत छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। महज चार साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और धीरे-धीरे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगीं। इस उम्र में जहां बच्चे खेलते-कूदते हैं, वहीं मीना कैमरे के सामने काम कर रही थीं। यह संघर्ष ही उनके भीतर एक गहराई लेकर आया, जो बाद में उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बनी। जैसे-जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, उन्होंने कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें 'बैजू बावरा', 'परिणीता', 'साहिब बीबी और गुलाम' और 'पाकीजा' जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके किरदार अक्सर दुख, त्याग और दर्द से भरे होते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती थी, जो दर्शकों के दिल को छू जाती थी। यही वजह थी कि लोग उन्हें 'ट्रेजेडी क्वीन' कहने लगे। उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। मीना कुमारी को फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक खुशहाल नहीं रह पाया। धीरे-धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं और दोनों अलग हो गए। इस टूटे रिश्ते ने मीना कुमारी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अकेलेपन और मानसिक तनाव ने उन्हें धीरे-धीरे शराब की ओर धकेल दिया। यह आदत उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगी। कहा जाता है कि वह डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थीं। उनकी जिंदगी में शोहरत, पैसा और नाम तो सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। यही वजह थी कि उनकी असल जिंदगी भी उसी दर्द से भरी रही, जिसे वह पर्दे पर निभाती थीं।

महज 39 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत लीवर सिरोसिस के कारण हुई। इतनी कम उम्र में उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था।

मीना कुमारी के वो यादगार गाने, जो आज भी हर दिल की धड़कन हैं

बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी बाद में 'ट्रेजेडी क्वीन' नाम से मशहूर हुईं। अभिनेत्री ने करीब 30 साल के फिल्मी सफर में कई यादगार किरदार निभाए और एक शानदार विरासत छोड़ गईं। उनकी अदाकारी के साथ-साथ फिल्मों के गीत भी आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी याद में हम आपको बेहतरीन गानों के बारे में बताते हैं, जिनमें से कुछ आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। अजीब दास्तां है ये : यह गाना साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल अपना और प्रीत पराई' के लोकप्रिय गीतों में शुमार हैं। गाने को शैलेंद्र ने लिखा, जबकि शंकर-जयकिशन ने संगीतबद्ध किया और लता मंगेशकर ने गाया है। मीना कुमारी और राज कुमार पर फिल्माया गया यह गीत अनकहे प्यार, दिल की उलझनों और भावनात्मक तकलीफ को बहुत खूबसूरती से बयां करता है।

'इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा': 1972 में आई फिल्म 'पाकीजा' में मीना कुमारी ने इस गाने पर डांस किया था। मीना कुमारी की अदाकारी में इस गाने का जादू और भी बढ़ा दिया था। यह गाना 1956 में लिखा गया था, लेकिन फिल्म में कमाल अमरोही ने इसे शाही अंदाज में पेश किया था।

'चलते-चलते यूं ही कोई मिल गया था' – फिल्म पाकीजा का यह दूसरा गीत भी लता मंगेशकर ने ही गाया था। मीना कुमारी ने बीमार होने के बावजूद इस गाने को फिल्माया था। यह उनकी आखिरी फिल्मों में से एक थी। गाने में एक अचानक हुई मुलाकात और उसके बाद की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। यह गाना मीना कुमारी की अदाकारी और भावपूर्ण अभिनय का शानदार मिश्रण है।

हम तेरे प्यार में सारा आलम : फिल्म 'दिल एक मंदिर' का यह गाना मीना कुमारी की निस्वार्थ प्रेम की कहानी को दर्शाता है। लता मंगेशकर की आवाज में गाया गया यह गीत शंकर-जयकिशन के संगीत और हसरत जयपुरी के बोलों से सजा है। यह गाना एक लव ट्रायंगल पर आधारित है, जहां सीता (मीना कुमारी) अपने पति राम (राज कुमार) के कैंसर का इलाज कराते हुए उनके डॉक्टर धर्मेश (राजेंद्र कुमार) के प्रति अपनी भावनाओं को छुपाती हैं। मीना कुमारी की फिल्में और गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। उनकी अदाकारी में एक खास तरह का दर्द था, जो दर्शकों को सीधे दिल से जुड़ता था।

अक्षय कुमार ने शेयर किया जीवन का सबसे बड़ा सबक, बताया कैसे सच होते हैं सपने

जिंदगी में अक्सर चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होतीं। कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई चीज हमारी क्षमता या पहुंच के बाहर है। इस बात को हाल ही में टीवी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के हालिया एपिसोड में अभिनेता अक्षय कुमार ने बहुत ही आसान तरीके से शो के एक कंटेस्टेंट को समझाया। दरअसल, शो के दौरान कंटेस्टेंट स्तुति ने कहा कि उसे लगता है कि कुछ लोग 'उसकी लीग' से बाहर हैं। स्तुति ने बताया कि शाहरुख खान हमेशा से उसके क्रश रहे हैं और जब शाहरुख खान ने गौरी खान से शादी की थी, तो उसका दिल टूट गया था। फिर, उसने सोचा कि अगर शाहरुख नहीं तो आर्यन खान सही, लेकिन बाद में उसे लगा कि आर्यन खान भी उसकी लीग से बहुत बाहर हैं।

अक्षय कुमार ने स्तुति की इस बात को सुनकर अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हर अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी को भी यह सोचकर सीमित नहीं रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति या सपना उसकी पहुंच से बाहर है। अक्षय ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि उनकी शादी ट्विंकल खन्ना से हुई है। ट्विंकल खन्ना दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं।

अक्षय ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा, जब मैं छोटा था, तो मेरे पापा और मम्मी मुझे कंधों पर बिठाकर कार्टर रोड और बैंडस्टैंड घुमाने ले जाते थे। उस समय राजेश खन्ना जी की गाड़ी वहां से गुजरती थी। तब वे मेरे ससुर नहीं थे, सिर्फ एक बड़े स्टार थे। उस समय हम उन्हें दूर से देखा करते थे।

उन्होंने आगे कहा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी शादी उनकी बेटी से हो जाएगी। उस समय तो मैंने भी इसकी कल्पना नहीं की थी।

अक्षय कुमार ने जोर देते हुए कहा कि असल में कोई भी चीज हमारी पहुंच से बाहर नहीं होती। उन्होंने बताया कि बचपन में राजेश खन्ना को देखने वाले छोटे लड़के को आजकल लोग उनके दामाद के रूप में जानते हैं। यह उदाहरण देकर उन्होंने साबित किया कि जिंदगी में सपने और मौके कभी भी हकीकत बन सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बंगाल चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए लिएंडर पेस

नई दिल्ली। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका यह कदम सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा नेता सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। पेस का भाजपा में शामिल होना पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। फिलहाल वहां चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। इस मौके पर रिजिजू ने कहा, लिएंडर पेस का भाजपा परिवार में शामिल होना ऐतिहासिक है। वहीं लिएंडर ने इसे अपने जीवन का सबसे खास दिन बताया। उन्होंने कहा, यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह मेरे लिए खेल और युवाओं की सेवा करने का बड़ा अवसर है।

सोनिया गांधी को सर गंगा राम अस्पताल से मिली छुट्टी

नईदिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी, जिन्हें 24 मार्च को बुखार के कारण सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मंगलवार को आगे के इलाज और घर पर निगरानी के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु की देखरेख में उनका एंटीबायोटिक्स से इलाज किया गया और इलाज का उन पर अच्छा असर हुआ। इससे पहले डॉक्टरों ने बताया था कि सोनिया गांधी की हालत में उत्कृष्ट सुधार हुआ है और अब वे पूरी तरह से ठीक हैं। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला लिया जाएगा। बुखार होने के बाद उन्हें 24 मार्च को रात करीब 10:22 बजे सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार, गांधी को अभी भी इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, जो कुछ और दिनों तक जारी रहेंगी, हालांकि उनके सभी पैरामीटर सामान्य सीमा के भीतर हैं।

पुडुचेरी चुनाव में एनडीए की जीत पक्की : के. अन्नामलाई

पुडुचेरी। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को आगामी 2026 पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संभावनाओं के प्रति आशा व्यक्त की। पुडुचेरी हवाई अड्डे पर बोलते हुए, उन्होंने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास की सराहना की और पुडुचेरी को विकास सूचकांकों में अग्रणी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्र- व्यापार, शिक्षा, आध्यात्मिकता और पर्यटन- के साथ विकास रणनीति को दोहराया और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे जमीनी स्तर पर संपर्क मजबूत करने तथा जनसमर्थन को वोटों में बदलने का आग्रह किया।

बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ याचिका खारिज

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। राज्य में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों से राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ेगा और निर्वाचन आयोग के आदेशों को निरस्त करने का अनुरोध किया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना चार मई को की जाएगी।

भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए जारी की चौथी लिस्ट

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें उत्तर 24 परगना जिले की बागदा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही, भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए 287 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनके लिए मतदान दो चरणों में होगा। पार्टी ने मैनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है और कौशिक रॉय के स्थान पर दलीम रॉय को मैदान में उतारा है। पार्टी ने हावड़ा दक्षिण से श्यामलाल हाटी, नटबारी से गिरिजा शंकर रॉय और सीताई से आशुतोष बर्मा को उम्मीदवार बनाया है। उत्तम कुमार बनिक मगराहट पुरबा से, देबांशु पांडा फाल्टा से, देबाशीष धर सोनारपुर उत्तर से और रंजन कुमार पॉल पंचला से चुनाव लड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, संतोष पाठक, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, को पार्टी ने कोलकाता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है।

असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने जारी किये घोषणा-पत्र

क्या भाजपा के विकास मॉडल पर भारी पड़ेगी कांग्रेस की नकद की गारंटी?

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस ने अपने अपने घोषणापत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। एक ओर भाजपा ने विकास, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और अधिकारों के विस्तार को अपने अभियान का केंद्र बनाया है। ऐसे में दोनों दलों के घोषणापत्र की तुलना चुनावी दिशा को समझने में महत्वपूर्ण हो जाती है।

हम आपको बता दें कि गुवाहाटी में मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए पांच लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश का बड़ा वादा किया। इस घोषणापत्र में कुल 31 वादे शामिल हैं, जिनमें मूल निवासियों की जमीन, विरासत और सम्मान की रक्षा को प्रमुखता दी गई है। भाजपा ने बांग्लादेशी मियांओं द्वारा अतिक्रमित जमीन को वापस लेने, समान नागरिक संहिता लागू करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही है।

सीतारमण ने कहा कि भाजपा का यह घोषणापत्र पिछले एक दशक में हुए विकास पर आधारित है, जिसे कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल में हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में असम में शांति स्थापित हुई है और विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि अब कई युवा असमी विदेशों की नौकरियां छोड़कर राज्य में लौट रहे हैं, जो बढ़ते अवसरों का संकेत है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी

नीतियों के कारण असम लंबे समय तक अफस्पा के दायरे में रहा।

इसके विपरीत कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पांच प्रमुख गारंटी पेश की हैं, जो सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नौबोइचा में आयोजित जनसभा में घोषणापत्र जारी करते हुए महिलाओं के लिए बिना शर्त मासिक आर्थिक सहायता का बड़ा वादा किया। कांग्रेस का कहना है कि हर महिला को सीधे बैंक खाते में मासिक धनराशि दी जाएगी, साथ ही उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए पचास हजार रुपये की सहायता भी मिलेगी।

कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा दी जा रही सहायता शर्तों से बंधी होती है, जबकि उनकी योजना पूरी तरह बिना शर्त होगी। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रत्येक परिवार को पच्चीस लाख रुपये तक का नगद रहित स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है।

भूमि अधिकार के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने एक लाख नहीं बल्कि दस लाख भूमिपुत्रों को स्थायी जमीन का पट्टा देने का वादा किया है, जिससे लोगों को हर साल कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने एक हजार दो सौ पचास रुपये देने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है।

कांग्रेस ने न्याय के मुद्दे को भी प्रमुखता दी है। पार्टी ने दिवंगत जुबीन गर्ग मामले में सौ दिनों के भीतर न्याय दिलाने का वादा किया है और पूरे मामले की साजिश का खुलासा करने की बात कही है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा, जिसमें दोषियों को पांच साल तक की सजा दी जाएगी।

दोनों घोषणापत्रों की तुलना करें तो भाजपा का फोकस बड़े स्तर पर विकास, निवेश और कानून व्यवस्था पर है, जबकि कांग्रेस सीधे आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और अधिकार आधारित योजनाओं पर जोर दे रही है। भाजपा जहां दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा और स्थिरता की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस तत्काल राहत और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रही है।

हम आपको बता दें कि असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा और मतगणना चार मई को की जाएगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता विकास बनाम गारंटी के इस मुकाबले में किसे प्राथमिकता देते हैं। देखा जाये तो यह चुनाव न केवल असम की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देगा।

केरलम में एलडीएफ और यूडीएफ की मैच फिक्सिंग होगी खत्म, जनता कमल खिलाएगी : नितिन नबीन

तिरुवनंतपुरम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने केरलम के एलडीएफ और यूडीएफ पर राजनीतिक खेल-खेल में हेराफेरी का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा के बढ़ते वोट शेयर से उसे जीत मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे पर तीखा हमला करते हुए उन पर सत्ता में बने रहने के लिए एक-दूसरे का समर्थन और आलोचना करके खेल-खेल में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए नबीन ने केरल में भाजपा के बढ़ते समर्थन पर प्रकाश डाला और बताया कि पार्टी का वोट शेयर 2% से बढ़कर 20% हो गया है, जो इसकी निरंतर प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य अब केवल केरल से विकसित केरल बनने की ओर अग्रसर है। नबीन ने कहा कि इस बार भाजपा केरल में कमल खिलाएगी। यहां की जनता से हमें जो समर्थन मिल रहा है - 2% वोट शेयर से 20% तक पहुंचना - हमारी प्रगति को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो कभी केवल केरलम था, अब विकसित केरलम के रूप में आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 70 वर्षों से अधिक समय से केरल की राजनीति एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मैच फिक्सिंग के चक्र से प्रभावित रही है। उनके अनुसार, दोनों गठबंधन एक-दूसरे पर आरोप लगाकर बारी-बारी से सत्ता में आते रहे हैं, और जनता अब इस पैटर्न को अच्छी तरह समझ चुकी है। नबीन ने जोर देकर कहा कि केरल की जनता इन मैच फिक्सर्स को नकारने और उन्हें सत्ता से बेदखल करके इस राजनीतिक चक्र को समाप्त करने के लिए तैयार है। नबीन ने कहा कि बहुत लंबे समय से - पिछले 70 वर्षों से - एलडीएफ और

यूडीएफ के बीच तथाकथित मैच फिक्सिंग की राजनीति जारी है। अब केरल की जनता इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये मैच फिक्सर्स, जो एक-दूसरे पर आरोप लगाकर सत्ता और विपक्ष में बारी-बारी से आते हैं, जनता द्वारा अच्छी तरह समझ लिए गए हैं। केरल की जनता अब इसका जवाब देगी और इन मैच फिक्सिंग ताकतों को सत्ता से हटा देगी।

केरलम में पीएम मोदी चाहते हैं एलडीएफ की जीत : राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) जीते। कन्नूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त ताकत से लड़ रहा है। यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे सीपीआई (एम) के दो पूर्व नेता - वी कुन्हीकृष्णन और टी के गोविंदन - भी मंच पर मौजूद थे।

राहुल गांधी ने चुनाव को विचारधाराओं की लड़ाई बताया और वामपंथी और भाजपा के बीच एक असामान्य गठबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है - एक

सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे की और दूसरी यूडीएफ की। पहली बार हम भाजपा और वाम मोर्चे के बीच साझेदारी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि एक वामपंथी दल एक अति दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कर रहा है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएँ एक-दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं।

गांधी ने कहा कि तो सवाल यह है कि एक वामपंथी दल एक दक्षिणपंथी दल के साथ गठबंधन कैसे कर सकता है? यह एक पहेली की तरह है। उन्होंने पूछा कि इस पहेली के कुछ जवाब मंच पर मौजूद हैं। आज यहाँ सीपीआई(एम) के दो दिग्गज नेता मौजूद हैं। वे हमारे मंच पर क्यों बैठे हैं, सीपीआई(एम) और मुख्यमंत्री के लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे? गांधी ने आरोप लगाया कि जिसे आज वाम मोर्चा कहा जाता है, वह अब न तो वामपंथी है और न ही मध्यमार्गी। उन्होंने कहा कि दरअसल, वे भाजपा के साथ इसलिए साझेदारी कर रहे हैं क्योंकि वे कॉरपोरेट पार्टियां हैं। वे अब जनता की पार्टियां नहीं रहीं। इसका सबूत अब मंच पर मौजूद है। वामपंथी विचारधारा वाले लोग कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी उनका समर्थन कर रही है। केरल में भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्य जगहों पर धर्म और मंदिरों के बारे में अक्सर बोलते हैं, लेकिन केरल में सबरीमाला सोने की चोरी का मुद्दा उठाने से बचते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला आज

नईदिल्ली। आईपीएल 2026 के पांचवें मुकाबले में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। लखनऊ और दिल्ली के बीच इस लीग में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है।

आईपीएल में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 4 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, जबकि 3 मुकाबलों में लखनऊ को जीत मिली हुई है। आईपीएल 2025 में इन दोनों टीमों के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों ही बार दिल्ली कैपिटल्स विजयी रही थी। दिल्ली अपने इस दबदबे को इस सीजन भी कायम रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

दिल्ली की टीम इस सीजन काफी संतुलित नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में टीम के पास केएल राहुल का अनुभव मौजूद है। राहुल का प्रदर्शन पिछले सीजन कमाल का रहा था और उन्होंने 13 मैचों में 149 के स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाए थे। राहुल के जोड़ीदार के तौर पर पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है। अभिषेक पोरेल ने भी आईपीएल 2025 में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया था। पोरेल ने 13 मैचों में 146 के स्ट्राइक रेट से 301 रन बनाए थे। करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर से भी इस सीजन टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मिलर के आने से टीम का मध्यक्रम और ज्यादा संतुलित दिख रहा है। समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा फिनिशर की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स का टॉप ऑर्डर काफी दमदार दिख रहा है। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम से इस सीजन भी टीम को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं, निकोलस पूरन अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

ईरान युद्ध से भारत की जीडीपी को झटका!

नईदिल्ली। ईरान युद्ध अगर अगले वित्त वर्ष तक जारी रहता है, तो भारत की रीयल जीडीपी ग्रोथ में करीब 1 फीसदी की कमी आ सकती है, जबकि खुदरा महंगाई दर करीब 1.5 फीसदी तक उछल सकती है। ईवाई की एक रिपोर्ट में यह जानकारी में सामने आई है। ईवाई की इकॉनमी वॉच रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सटाइलस, पेंट, केमिकलस, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और टायर जैसे रोजगार-प्रधान सेक्टर्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इन सेक्टर्स में रोजगार या आय में कमी आने से कुल मांग भी कमजोर हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव से सप्लाई और डिमांड दोनों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत अपनी करीब 90 फीसदी कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है और नेचुरल गैस व फर्टिलाइजर्स के लिए भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

नए वित्त वर्ष में लागू होगा नया आयकर कानून

नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश का आयकर ढांचा बड़े बदलावों के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा, जो करीब छह दशक पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम, प्रक्रियाओं और नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एकल टैक्स ईयर की शुरुआत है, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। रिटर्न फाइल करने की समयसीमा में भी बदलाव किया गया है। जहां सैलरीड वर्ग के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन बरकरार है, वहीं गैर-ऑडिट मामलों जैसे स्वरोजगार और प्रोफेशनल्स के लिए अब 31 अगस्त तक का समय मिलेगा।

एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच बड़ा राहत वाला विकल्प

नईदिल्ली। ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसका असर अब भारत में एलपीजी उपलब्धता पर भी दिखने लगा है। इसी बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 5 किलो के 'छोटू' एलपीजी सिलेंडर का विकल्प पेश किया है। कंपनी के अनुसार, यह सिलेंडर बिना बुकिंग के आसानी से उपलब्ध है और इसे तुरंत लिया जा सकता है। आईओसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, बिना इंतजार के झट से एलपीजी की जरूरत है? छोटू से मिलिए। इंडेन का 5 किलो का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर आपके करीब इंडेन गैस एजेंसी पर उपलब्ध है। कॉम्पैक्ट, सुविधाजनक और आसानी से उपलब्ध यह सिलेंडर को ऐसे समय के लिए डिजाइन किया गया है जब आपको बिना देरी के विश्वसनीय कुकिंग सहयोगी की जरूरत हो।

मिडिल ईस्ट तनाव पर आईएमएफ की चेतावनी

वाशिंगटन। मीडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गंभीर चेतावनी दी है। आईएमएफ के मुताबिक, यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है और हाल ही में उबर रही अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार थम सकती है। आईएमएफ का कहना है कि इस संकट का असर अलग-अलग देशों पर अलग होगा लेकिन कुल मिलाकर दुनिया को कम आर्थिक विकास और ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर एशिया और अफ्रीका के तेल आयातक देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तनाव का सबसे बड़ा असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर दिख रहा है, जहां से दुनिया की करीब 25-30% तेल और 20% गैस सप्लाई गुजरती है।

वैश्विक संकट रातोंरात खत्म नहीं होते : हर रसोई तक पहुंचता पश्चिम एशिया युद्ध

पत्रलेखा चटर्जी

पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध का भारत के मिड-डे मील से क्या लेना-देना है? इसका संक्षिप्त उत्तर है-बहुत गहरा। 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी है, जिसकी लपटें अब तेजी से फैल रही हैं। तीन हफ्तों के भीतर ही युद्ध दूर-दराज की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर रहा है और करोड़ों बच्चों व परिवारों के जीवन पर असर डाल रहा है। दुनिया भर में ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, जिससे ऐसी असमानता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जो पहले कभी नहीं देखी गई।

रसोई गैस (एलपीजी) वह ईंधन है, जिससे भारत में लाखों घरों के चूल्हे जलते हैं। यही गैस प्रधानमंत्री पोषण (पीएम पोषण) मिड-डे मील योजना के तहत लगभग 11 करोड़ बच्चों के लिए भोजन बनाने में उपयोग होती है, और आंगनवाड़ी केंद्रों (जहां छह साल से कम उम्र के लाखों बच्चों को पूरक पोषण मिलता है) की रीढ़ है।

फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाले संकीर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। इसी से होकर दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल और गैस गुजरती है। ऐसे में, युद्ध के कारण होर्मुज से होने वाली आपूर्ति पर पड़े दबाव ने गैस सिलिंडरों की उपलब्धता को प्रभावित किया है। नतीजतन, कई आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों की रसोइयों में या तो गैस की अनियमित आपूर्ति हो रही है या उन्हें मजबूरन लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है।

भारत में मिड-डे मील योजना से जुड़े लगभग 27 लाख रसोइए और सहायक कर्मियों में से 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। इनमें से कई महिलाएं तो हालिया संकट से पहले भी लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर थीं। अब एलपीजी संकट गहराने के साथ और अधिक महिलाएं पारंपरिक चूल्हों की ओर लौट रही हैं।

दिल्ली समेत देश के कई शहरों की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोग भी एक बार फिर चूल्हों की ओर लौटने को मजबूर हैं। सूरत के टेक्सटाइल उद्योगों में कामकाज धीमा पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और ओडिशा से आए प्रवासी मजदूर गैस सिलिंडर की किल्लत और महंगाई के कारण अपने घरों को लौट रहे हैं। आम परिवारों पर भी महंगाई की मार स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि घरेलू (गैर-सब्सिडी) एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हो चुकी है, जबकि काले बाजार में इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बाइक से सामान पहुंचाने वालों का मुनाफा खत्म हो रहा है, और एफएमसीजी कंपनियां डिटर्जेंट, बिस्कुट, टूथपेस्ट और पैकेजिंग जैसे उत्पादों की लागत बढ़ाने की चेतावनी दे रही हैं।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भले ही सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर मिल रहा हो, पर लंबी देरी के कारण उन्हें भी लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि, जिन लोगों के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी), महंगे दामों पर गैस खरीदने की क्षमता, या फिर इंडक्शन चूल्हे के साथ भरोसेमंद बिजली है, वे इस संकट से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। पर अधिकांश लोगों के पास ऐसे विकल्प नहीं हैं।

गौरतलब है कि भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, और इनका करीब 90 फीसदी हिस्सा होर्मुज मार्ग से होकर ही गुजरता है। इस मार्ग में आई बाधाएं, भारत में मौजूदा एलपीजी संकट की एक बड़ी वजह बन गई हैं। पिछले हफ्ते, दो भारतीय एलपीजी टैंकर होर्मुज पार कर गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचने में सफल रहे। इनके जरिये करीब 92,712 टन एलपीजी भारत पहुंची, जो देश की एक दिन की जरूरत के बराबर है। खबरें हैं कि कुछ और टैंकर भारत आ सकते हैं। यह भारत की सक्रिय कूटनीति और तेहरान के साथ सीधे तालमेल का नतीजा है। इन सबके बावजूद यह संकट रातोंरात खत्म होने वाला नहीं है। भारत हर साल लगभग 3.1 से 3.3 करोड़ टन एलपीजी की खपत करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन इसकी केवल लगभग 40 फीसदी जरूरत ही पूरी कर पाता है।

पीएम आवास निर्माण में देश में अव्वल होने पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने जताया हर्ष

सम्मान और आत्मनिर्भरता भी हो रहे सुनिश्चित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल करते हुए पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। राज्य ने न केवल सर्वाधिक आवास निर्माण पूर्ण कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है, बल्कि मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने हर्ष जताते हुए प्रदेशवासियों एवं हितग्राहियों को शुभकामनाएँ दी।

उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत छत्तीसगढ़ ने 'एसएनए स्पर्श' के माध्यम से देश में सर्वाधिक व्यय कर उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्ष 2016 में योजना के प्रारंभ से अब तक एक ही वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक आवास निर्माण का रिकॉर्ड भी इसी वर्ष दर्ज किया गया है, जो राज्य की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि आवास से आजीविका' के अभिनव प्रयास के अंतर्गत निर्माण सामग्री की आपूर्ति से हजारों महिलाओं को रोजगार मिला है। जिसमें रोजगार पाकर 9000 से अधिक बिहान दीदियाँ लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं। इसके साथ ही इस वर्ष 6000 से अधिक राजमिस्त्रियों को आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो देश में सर्वाधिक है।

उल्लेखनीय है कि इन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों में 1400 महिलाएँ एवं 400 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं, जो मुख्यधारा में जुड़कर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। पीएम आवास ग्रामीण के हितग्राहियों को स्थायी आजीविका से जोड़ने हेतु महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कार्य भी कराए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ग्रामीण विकास और गरीबों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से न केवल पक्के घरों का सपना साकार हो रहा है, बल्कि लोगों की आजीविका, सम्मान और आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित हो रही है। राज्य आगे भी इसी गति और प्रतिबद्धता के साथ विकास की नई ऊँचाइयों को छुएगा।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 : कर्नाटक की मनीषा जोंस सिद्दी ने जीता गोल्ड

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत आज सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले चार दिनों से जारी कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन आज हुआ। प्रथम ऐतिहासिक संस्करण में कर्नाटक की बेटी मनीषा जोंस सिद्दी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कुश्ती के 76 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। अभावों के बीच पली-बढ़ी मनीषा की यह जीत केवल एक पदक नहीं, बल्कि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प की विजय है।

मनीषा का खेल जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वह पाँचवीं कक्षा में थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बावजूद, उनकी माँ ने हार नहीं मानी और अकेले दिन-रात मेहनत करके मनीषा के सपनों को पंख दिए। पूर्व में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीत चुकीं मनीषा के करियर का यह पहला गोल्ड मेडल है। अपनी सफलता को साझा करते हुए मनीषा ने कर्नाटक के डिवाइस स्पोर्ट्स हॉस्टल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, हॉस्टल के कोच और साथी खिलाड़ियों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। मेरा बड़ा भाई मेरा मार्गदर्शक रहा है, वहीं छोटा भाई, जो खुद एक राज्य स्तरीय एथलीट है, वह मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। मनीषा ने केंद्र सरकार और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जैसे मंच से जनजातीय समुदाय के बच्चों को अपनी विशेष पहचान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है।

उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा मैच के दौरान सुरक्षा, भोजन और यातायात की व्यवस्था बेहतरीन थी। छत्तीसगढ़ के लोगों का व्यवहार और यहाँ का माहौल खिलाड़ियों के लिए अत्यंत सुखद है। स्वर्ण पदक की चमक के साथ मनीषा की निगाहें अब भविष्य की बड़ी चुनौतियों पर हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर मिली इस सफलता से उत्साहित मनीषा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में जुटी हैं। उनका अंतिम लक्ष्य विश्व पटल पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाना है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत आज सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले चार दिनों से जारी कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन आज हुआ। प्रथम ऐतिहासिक संस्करण में कर्नाटक की बेटी मनीषा जोंस सिद्दी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कुश्ती के 76 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। अभावों के बीच पली-बढ़ी मनीषा की यह जीत केवल एक पदक नहीं, बल्कि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प की विजय है।पिता के निधन के बाद माँ बनीं संबल: मनीषा का खेल जीवन चुनौतियों से भरा रहा है।

सीएम साय ने किया धरसींवा में आधुनिक तहसील कार्यालय का लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर जिले के धरसींवा में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का लोकार्पण किया। यह पहल प्रशासनिक सेवाओं को आमजन के और अधिक निकट, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन का मूल उद्देश्य यही है कि नागरिकों को उनकी जरूरत की सेवाएं समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से मिलें। धरसींवा का यह नया तहसील कार्यालय इसी संकल्प को साकार करता है। उन्होंने कहा कि इस भवन के शुरू होने से क्षेत्र के नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों में अब अधिक सुविधा और तेजी मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर नागरिक को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध हो।

नवनिर्मित तहसील कार्यालय में नायब नाजिर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, माल जमार, नकल शाखा, कानूनगो कक्ष, भुइयां एवं भू-अभिलेख शाखा जैसी आवश्यक इकाइयों के साथ-साथ लोक सेवा केंद्र और आधार केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल सहित अन्य बुनियादी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि इस आधुनिक तहसील कार्यालय का निर्माण 66.20 लाख रुपये की लागत से किया गया है, जो क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2 अप्रैल से आगरा में

रायपुर। आगरा में 2 से 4 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए छग पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा से 52 खिलाड़ी कल ट्रेन से रवाना होंगे। जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अधिक से अधिक मेडल छग के लिए लाने की बधाई दी। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव मानिक ताम्रकार ने बताया कि टीम में रोहन तिवारी, जय नारायण अग्रवाल, प्रतीक चंद्राकर, सत्यजीत पृष्टि, भास्कर साहू, देवेंद्र चोरका, मुनींद्र साहू, नीतेश्वर तराम, रॉबिन चौहान, यस वर्धन सोनी, आशीष निषाद, भूमि नेभवानी, यस राजपूत, हर्ष बैरागी, विनय वैष्णव, संदीप जायसवाल, शुभम वैष्णव, संतोष बंधाते, श्रीकांत अड़े, मंजू इंगले, नवीन चंद्र कपूर, कमला देवी मांगतानी, दिव्यांग खिलाड़ी में किशन लाल, साहिल, उदय कुमार, ललित कुमार ठाकुर, दुष्यंत ध्रुव, एलन बांसोड, किशन कश्यप, भूपेंद्र राजपूत, हरि सोनवानी, देव सिंह अहीरे, राजेंद्र ग़ेहानी, किशोर साहू, अजय ओगरे, विजय कुमार कौशिक, मुकेश लहरें, दिलदार सिंह कवर, जीवन लाल राठिया, अशोक कुमार पटेल, गोस्वामी, ब्रिज नंद पैकरा, सुंदर कुशराम, चंद्रपाल मानिकपूरी, बजरंग पटेल, टीकम सिंह सोरी, हरीश कुमार, तोरण सिंह, छोटी मेहरा, मनीषा, चतुर दास सोनवानी शामिल है।

इसके अलावा दिव्यांग खिलाड़ी के कोच एवं मैनेजर किशन लाल एवं महिला पुरुष खिलाड़ी के कोच एवं मैनेजर मुनींद्र साहू होंगे।

पावर कंपनीज से ईडी आलोक सिंह एवं एजीएम मिश्र को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ से कार्यपालक निदेशक (वित्त) आलोक सिंह एवं अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्रा सहित कुल 8 अधिकारी-कर्मचारियों को अधिवार्षिकी पूर्ण होने पर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई।

पॉवर कंपनीज़ के मुख्यालय सेवा भवन में आयेजित समारोह में प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर तथा निदेशक आरए पाठक ने सेवानिवृत्त ईडी सिंह एवं एजीएम मिश्र को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभव ने पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति प्रदान की है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दोनों अधिकारियों ने तीनों कंपनियों में सेवाएं देते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आलोक सिंह अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पावर कंपनी निरंतर प्रगति कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से कंपनी में किये गए नवाचार और उपायों से काफी सुधार हुआ है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की 14 वीं रिपोर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ए ग्रेड मिला है। मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता से लेकर अविभाजित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज और मुख्यमंत्री सचिवालय में 24 वर्षों तक की यात्रा चुनौतियों से भरी रही, किन्तु सबके सहयोग से सभी कार्य सफलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जा सके।

दोनों अधिकारियों ने प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकगण सर्व वी.के. साय, सी.एल. नेताम, एम.एस. चौहान, आर.पी. नामदेव, संदीप मोदी, एम.आर. बागड़े, मनीष गुप्ता उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

नक्सलवाद की पोषक तो भाजपा की नीतियां थी : बैज

रायपुर। भाजपा द्वारा नक्सल मामला पर अपनी पीठ थपथपाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद भाजपा के रमन सरकार के समय पूरे प्रदेश फैला जब राज्य में 2003 में भाजपा की सरकार बनी तब नक्सलवाद बस्तर के 3 ब्लॉकों तक ही सीमित था। रमन राज के 15 सालों में नक्सलवाद बस्तर के तीन ब्लॉकों से निकलकर 14 जिलों तक पहुंच गया। इन 15 सालों के अंत के 4 साल तक केंद्र में नरेन्द्र मोदी की भी सरकार बन चुकी थी। प्रधानमंत्री इस तथ्य को जान ले राज्य में नक्सलवाद की जिम्मेदार भाजपा की फासीवादी सोच और नीतियां है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राज में 6 अप्रैल 2010 में जिला दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में 76 सीआरपीएफ जवान, 24 अप्रैल 2017 में जिला सुकमा के दुर्गापाल 25 सीआरपीएफ जवान शहीद, 25 मई 2013 दरभा के जीरम, जिला बस्तर में महेन्द्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल सहित 30 लोग शहीद, 29 जून 2010 धोडाई जिला नारायणपुर 27 पुलिस जवान शहीद, 17 मई 2010 दंतेवाड़ा यात्री बस में 36 लोग शहीद , 12 जुलाई 2009 मदनवाडा एसपी चौबे सहित 29 पुलिसकर्मी शहीद, 09 जुलाई 2007 उपलमेटा एर्राबोर 23 पुलिस कर्मी शहीद, 15 मार्च 2007 रानीबोदली बीजापुर 55 जवान शहीद हुये थे।

नक्सलवाद समाप्ति के सरकार के दावे पर कांग्रेस के 10 सवाल

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश से नक्सलवाद समाप्ति की घोषणा किया था। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार से सवाल पूछा कि- 31 मार्च बीत गया, क्या साय सरकार इस बात की अधिकारिक घोषणा करेगी, प्रदेश से नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हो चुका है, अब प्रदेश का कोई भी इलाका नक्सल प्रभावित नहीं है? क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी, प्रदेश नक्सल के नाम से हो रही हिंसा से मुक्त हो चुका है? अब प्रदेश में कोई नक्सल हिंसा नहीं होगी? नक्सलवाद समाप्ति के लिए सरकार ने क्या पैमाना माना था और उनमें से कितने पैमाने पूरे हो चुके है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अब बस्तर में किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा? अब बस्तर का आम आदिवासी मारा नहीं जाएगा ?यदि नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो राज्य सरकार ने अभी तक बस्तर से कितने सुरक्षाबलों के कैंप हटाना शुरू किया? कितने सुरक्षा बलों की बटालियन की बस्तर से वापसी करना शुरू किया गया? नागरिक बस्तर में कहीं भी, किसी भी समय बेरोक-टोक आ जा सकते है, सरकार उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेगी क्या? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। क्या अब नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष आदिवासियों का एनकाउंटर नहीं होगा।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालो में भारी अव्यवस्था : ठाकुर

रायपुर। खून की कमी से जिला अस्पताल सूरजपुर में हुयी बच्चे को मौत पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के डॉक्टरों पर भड़कने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। मेडिकल कालेज, हास्पिटल, जिला अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय में मरीज ईलाज के लिये भटक रहे है। मरीजों से दुर्व्यवहार एवं इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत लगातार मिल रही है। इसके लिये जितना डॉक्टर दोषी है, उतना ही स्वास्थ्य मंत्री भी जिम्मेदार है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स की कमियां, दवाइयां, एक्सरे, सहित सभी प्रकार की जांच की सुविधा एक प्रकार से खत्म हो गई। जब मरीज के परिजन अस्पतालो की दुर्दशा पर शिकायत करते है, तब भाजपा सरकार के मंत्री सब कुछ बेहतर होने दावा कर शिकायतों को नजरअंदाज करते है। अब मंत्री राजवाड़े खुद ही डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रही है तो इन परिस्थियों के लिये ज़िम्मेदार कौन है? प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा अब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जब जिला अस्पताल में ईलाज की लापरवाही का आरोप लगा रही है।

श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन

रायपुर। श्री हनुमान जन्मोत्सव गुरुवार 2 अप्रैल को चौबे कालोनी स्थित श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा। सुबह मंदिर में श्री बजरंग बली का अभिषेक, पूजा-अर्चना व प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संध्या 5 बजे भजन प्रवाहक सचिन गुप्ता एण्ड पार्टी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। फूलों की वर्षा एवं बधाई उत्सव के साथ हनुमान जी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। संध्या 8 बजे संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व आरती की जाएगी। रात्रि 8.30 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में दीपक-नरेश केडिया ने बताया कि श्री चिंताहरण हनुमान मंदिर में विगत 4 वर्षों से प्रत्येक मंगलवार को संध्या 7.30 बजे से संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है जिसमें लगभग 600 लोग उपस्थित रहते है। पूरा परिसर जय श्री हनुमान, जय श्री राम के नारों से गूंजता है।पं. घनश्याम तिवारी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमानजी का जन्म हुआ था, हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई।

राज्यपाल से रेडियो संगवारी टीम ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में रेडियो संगवारी की टीम ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान टीम ने रेडियो संगवारी की परिकल्पना, उद्देश्यों तथा आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।टीम के संस्थापक श्री राहुल शर्मा ने बताया कि रेडियो संगवारी टीम द्वारा प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है और ऐसे प्रयास इसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने रेडियो संगवारी टीम को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया।इस अवसर पर रेडियो संगवारी टीम के डॉ. हेमंत सिरमौर, सुश्री श्रीया सिरमौर, श्री शिवनंदन सरोज, तिलका साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

बृजमोहन ने लोकसभा में उठाया 'एकल शिक्षक' स्कूलों का मुद्दा

नई दिल्ली/रायपुर। लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ समेत देशभर में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और छात्र-शिक्षक अनुपात में विसंगति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। श्री अग्रवाल ने सरकार से एकल शिक्षक स्कूलों को समाप्त करने की समय-सीमा और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर भी सवाल किए। सांसद श्री अग्रवाल ने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने 'पीएम श्री' योजना के तहत विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अल्प-उपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों के बिना केवल बिल्डिंग बना देने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। जिसपर जवाब देते हुए शिक्षा राज्य मंत्री जयन्त चौधरी ने जानकारियां साझा करते हुए बताया कि, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

अतः शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और उनकी तैनाती मुख्य रूप से राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। सेवानिवृत्ति और नामांकन में वृद्धि के कारण रिक्तियां एक सतत प्रक्रिया है, जिसे भरना राज्यों का दायित्व है। केंद्र सरकार 'समग्र शिक्षा' योजना के माध्यम से राज्यों को वित्तीय मदद दे रही है। विशेष रूप से पहाड़ी, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों (खासकर महिला शिक्षकों) के लिए आवासीय क्वार्टर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि शिक्षकों का प्रतिधारण बेहतर हो सके।

त्री ने यह भी बताया कि 'पीएम श्री' स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रति शिक्षक 2,500 तक की सहायता और DIET के माध्यम से 3 लाख तक का बजट आवंटित किया जा रहा है। 'निष्ठा' (हृद्धस्र॥ञ्ज॥) कार्यक्रम के जरिए शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि वर्ष 2024-25 के यूडाइज डेटा के अनुसार एकल शिक्षक स्कूलों की राज्य-वार सूची सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध है और केंद्र लगातार राज्यों को आरटीई मानकों के पालन हेतु निर्देशित कर रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ के वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि आकांक्षी जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए राज्यों की मॉनिटरिंग और सख्त की जाए।

भाठागांव में शराब दुकान के खिलाफ गुलाब वाला घेराव, शराबियों को गुलाब भेंट कर किया निवेदन

रायपुर। दक्षिण विधानसभा के भाठागांव क्षेत्र में संचालित देशी-विदेशी शराब दुकानों और अहातों के खिलाफ आज जन-आक्रोश फूट पड़ा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों क्षेत्रीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान का घेराव किया। प्रदर्शन का अनोखा पहलू यह रहा कि प्रदर्शनकारियों ने शराब खरीदने आए लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर गांधीवादी तरीके से शराब न खरीदने और नशा छोडने का विनम्र निवेदन किया।

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि भाठागांव बस्ती में स्वामी आत्मानंद स्कूल और वालफोर्ट सिटी जैसे रिहायशी इलाकों के पास शराब दुकानें खोलकर जनता की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सोनकर पारा, आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी और बीएसयूपी जैसे क्षेत्रों की महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। रिंग रोड और सर्विस रोड पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे छेड़छाड़, ट्रैफिक जाम, लूट, सड़क दुर्घटना और चाकूबाजी जैसी आपराधिक घटनाएं आम हो गई हैं। नीति और नीयत में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान विनोद ठाकुर, मनोज सोनकर, मो. आसिफ, सुरेश बाफना, शरद गुप्ता, ऋषि देवांगन, राजेश त्रिवेदी, मो. सिद्धिक, प्रवीण जैन, नरेंद्र ठाकुर, राजेंद्र जैन, श्रीमती गंगा यादव, श्रीमती ममता राय, श्रीमती प्रीति सोनी, जयश्री बरेलिया, प्रेरणा साहू, बानो खान उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.